पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

साप्ताहिक

समय माया

www.samaymaya.com

पंजीयन क्रमांक RNINDPM\HIN\20345/12/1/2006/TC

प्रधान संपादक-अजमेरा एस.पी.कुमार
B.COM., M.A., LLB, CAIIB, DLLLW&PM

cell : 9300755803-9425125569
Phone Fax : 91-731-2530859
Websites : www.samaymaya.com
www.geocities.com/samaymaya/jan09.pdf
www.geocities.com/corruption2india/corruptindia.html
www.geocities.com/corruption2india/corruptMP.html
E-mail : mwc@indiatimes.com
: linkdage@hotmail.com,
: linkadage@indiatimes.com
(c) all copyrights reserved with chief editor,do not publish any matter without prior permission.

वर्ष 1 अंक 53 इंदौर, सोमवार 16 फरवरी से 22 फरवरी 2009 तक पृष्ठ 8 मूल्य रु. 2/-

2 ✦कानून का पालन करवाने वाले खुद कानून से ऊपर

3 ✦ठेकेदारों को अरबों अग्रिम, इबंत

4 ✦33 अधिकारियों के विरुद्ध जांच हो

5 ✦लूट सके तो लूट पूरी है छूट

6 ✦महिला वैज्ञानिक का राष्ट्रहित में संघर्ष

7 ✦भूमाफिया डकार गए अरबों की जमीनें

26 जनवरी पर राष्ट्र के प्रधानमंत्री की बाइपास-नकारा, बीमार सिद्ध

राहुल को प्रधानमंत्री बनाने का षड्यंत्र

चूजे को बैठाकर इटली को सौंपी जाएगी कमान

राष्ट्र में शासन कर रही कांग्रेस और उसके सहयोगी गिरोहों की जालसाजियों से राष्ट्र की बुद्धिजीवी जनता अच्छी तरह देख चुकी है। आतंक के हथियार का किस तरह मीडिया और जनता का ध्यान परिवर्तित करवाने का षड्यंत्र भले ही जनता के समझ न आया हो, परंतु समय माया अपने प्रारंभ से ही इनके इस षड्यंत्रों की सच्चाई प्रगट कर रहा है।

अब आने वाले लोकसभा चुनावों को एक तरफा जीत कर चूजे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने और उसकी आड़ में बूढ़े, घाघ कांग्रेसी प्रणव, कमल, अर्जुन, चिंदबरम स्वयं सोनिया अपने जालसाजियों, धन बटोरने देश को गिरवी करने का काम बाखूबी अंजाम देंगे।

यह लाखों बुद्धिजीवी पाठकों की आशंका की राजीव को सत्ता सौंपने, इंदिरा की हत्या कर उन्हीं के प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात अंगरक्षकों ने की थी और सहानुभूति लहर में पूरा लोकसभा चुनाव जीत लिया गया था कि तर्ज पर आतंकवादियों, तमिल विद्रोही गुटों या अन्य तरह से सोनिया को निपटाकर, हत्या कर एक तरफा लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सहानुभूति लहर पैदा कर सोनिया को शहीद का दर्जा देकर राहुल के लिए वोट कबाड़े जाएं। बाद में राहुल की सत्ता, इटली के ननिहाल से चलाया जाकर, राष्ट्र में ईसाइयत को वृक्ष को सींचकर ईसाई धर्म का राजधर्म की तरह पालने-पोसने, फैलाने का कार्य बेरोकटोक किया जा सके। जैसा कि 21वीं

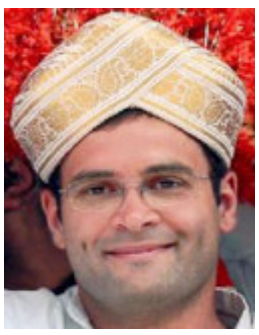

इसके लिए इंदिरा की हत्या की तरह सोनिया स्वयं को निपटाकर पूरे देश में सहानुभूति लहर पैदा करने का षड्यंत्र भी रच सकती है, कांग्रेस

सदी ईसाईयों की होगी। पोप की घोषणा का सच किया जा सकेगा, बेशक जो लिखा गया है उस षड्यंत्र में कहां क्या किया जा रहा है साधनों के समयाभाव में कुछ भी ज्ञात तो नहीं पर इस षड्यंत्र को अंजाम न केवल भारत में वरन कई जगह देशी विदेशियों के साथ चल रहा है।

कांग्रेसी गिरोह सफेद पोश डकैतों, जालसाजों, धूर्त गिद्धों की तो जमात है, जिसके पास नैतिकता और राष्ट्रीयता दिखाने और चिल्लाने का हथियार है, जबकि चरित्र से घोर अनैतिक सत्ताभोगी, देश हितों के विरुद्ध कार्यशाली रहे हैं। आखिर राष्ट्रहितों के विरुद्ध परमाणु समझौता केवल कमीशन खोरी के लिए ही किया गया। परमाणु समझौते, परमाणु बिजलीघर बनाने के लिए जानबूझकर ताप विद्युत घरों को केंद्र सरकार जानबूझकर पर्याप्त कोयला आपूर्ति नहीं कर रहा है और प्रादेशिक स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर बिजली की जानबूझकर कमी पैदा की जा रही है, तो मात्र दोनों हाथ लड्डू खाने और जनता को नोंचने के लिए; अभी गणतंत्र दिवस पर राष्ट्र के प्रधानमंत्री की बाईपास करवाकर जबकि यदि बाइपास यदि की ही जानी थी, दिस. प्रारंभ से लेकर अंत तक करवाकर प्रधानमंत्री 26 जनवरी का भाषण दे सकते थे, पर यह षड्यंत्र भी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का ही हिस्सा थी, यदि भाषण देते तो स्वाभाविक सा था चुनाव जीतने के लिए जनता के लिए कुछ तो घोषणाएं करने, कुछ लालच देते, **शेष पेज 2 पर**

दक्षिण एशिया के बारे में ओबामा भी बुश की राह पर

आवश्यक है कि अमेरिका पाक को सहयोग बंद करे

अमेरिका की पाकिस्तान को 7.5 अरब की सहायता

20-1-09 को दुनिया पर राज करने का सपना देखने वाले संकर प्रजाति के राष्ट्र अमेरिका में ईसाई पिता और ईसाई मान से जन्में अश्वेत ओबामा ने राष्ट्रपति का पदभार संभाल लिया है। पिछले दो सप्ताहों के लेखे-जोखे में कुछ आधारभूत तथ्य जो उभर कर सामने आए हैं उससे जो निष्कर्ष निकला है, वह अमेरिकी जनता को वित्तीय व्यवस्था वहां के औद्योगिक जगत को क्या देगा, वह स्पष्टतौर पर 3 माह बाद ही सामने आ सकेगा। इसके विपरीत मध्यपूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में ओबामा की नीतियों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान राष्ट्रपति अपने पूर्ववर्ती राष्ट्रपतियों के पद चिन्हों पर ही चलेंगे।

गाजा पट्टी लेबनान और इसरायल युद्ध में संयुक्त राष्ट्र ने भले ही लेबनान में युद्ध से हुई हजारों मौतों और घायलों को देखते हुए युद्ध विराम करवाने के प्रयास किए पर ओबामा चुप रहा, दूसरी तरफ अमेरिकी प्रशासन संयुक्त राष्ट्र भले ही पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित करे या आतंकवादियों की फसल पैदा करने वाला राष्ट्र कहे, परंतु ओबामा ने आते ही 7.5 अरब डालर की सहायता की घोषणा कर उस पाकिस्तानी आतंकवादी फसल को पैदा करते रहने के लिए खाद-पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था तो कर ही दी, अर्थात् ओबामा के आने से दक्षिण एशिया में भले ही दूसरे अन्य परिवर्तन हो जाएं परंतु आतंकी गतिविधियों में खास कुछ शेष पेज 2 पर

कांग्रेस विकसित संरक्षित स्वतंत्रतावादी तमिल टाइगर

क्यों चुप है कांग्रेस, श्रीलंका में तमिल संहार पर

बेचारी भारत सरकार एम्स में बचने के लिए हॉस्पिटलाइज्ड है

भारत में स्व. इंदिरा गांधी ने रायबरेली के इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किए जाने पर राष्ट्र में आपातकाल, 1974 में लगाया और जनता पर सरकारी तंत्र से भारी जुल्म करवाए, फलस्वरूप चुनाव हार गई। कांग्रेस की तानाशाह इंदिरा ने खालिस्तान के भिंडरा वाले को खड़ा कर आतंकवाद का बीज बोया। बाद में इस परंपरा का निर्वहन करते हुए स्व. राजीव गांधी ने अपने प्रधानमंत्रीत्व काल में 1985-86 में तमिलों के वर्चस्व का स्थापित करने और अपनी सल्तनत के पैर वहां पसारने के लिए प्रभाकरण और उसके साथियों को भारत की सेनाओं गुरिल्ला और कमांडो का प्रशिक्षण दिलवा कर वित्तीय और सामरिक सहायता देकर वहां जमाया। फिर भिंडरावाला की खालिस्तान फोर्स के विरुद्ध आप्रेशन ब्ल्यू स्टार चलाकर स्वर्ण मंदिर में अपनी सत्ता के चलते हजारों सिक्खों की हत्या की गई, जिन्होंने बाद में उसी के बंगले में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी। वही हाल तत्कालीन प्रधानमंत्री

राजीव गांधी ने मां के नक्शे कदम पर चल जब तमिलों ने खुलकर खून खराबा करना शुरू कर दिया तो भारत ने ही वहां अपनी शांतिरक्षक सेनाएं भेजकर तमिलों की शेष पेज 2 पर

पूर्व नियोजित षड्यंत्र था– बाइपास का बहाना

मनमोहन की बाइपास या 26 जनवरी की

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग के दिल की बाईपास सर्जरी ठीक गणतंत्र दिवस के एक दिन पूर्व की गई या पूर्ण नियोजित षड्यंत्र का हिस्सा थी और पूरी तरह से वास्तविकता या पूरा नाटक था, ताकि प्रधानमंत्री मनमोहन 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की परेड के बाद लालकिले से दिए जाने वाले भाषण की रस्म अदायगी में दुनिया के सामने और देश के सामने कुछ भी न कह सके।

इस नाटक की रूपरेखा 26-11-08 के हमले से उपजी विषम परिस्थितियों के चलते दिसम्बर के मध्य में ही ले लिया गया था, कि प्रधानमंत्री 26 जनवरी 09 को लाल किले से कोई भी भाषण न दें, क्योंकि वो अगर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराते हैं तो दोनों देशों की सेनाएं युद्ध के मैदान में आमने-सामने खड़ी है। दोनों ही परमाणु सम्पन्न राष्ट्र है। भारत परमाणुवीय मिसाइलों से हमले के बाद ही हमला

करेगा, उसके पहले अगर उसने दिल्ली जो पाकिस्तानी शाहीन 1,2,3 की मार में है, अगर हमला कर दिया तब क्या होगा? का डर भी कांग्रेसी सत्ता को सताता रहता है।

दूसरा लोकसभा चुनाव सामने है, अगर कोई घोषणा की जाती है, तो चार माह में ही पूरी करनी होगी। दूसरा जो भाषण दिया जाएगा स्वाभाविक है पूरा ही वोटों की राजनीति से प्रेरित और पूर्ण होगा, जो किसी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के किसी भी दल के विरोध में जाएगा तो भी नया बखेड़ा खड़ा होगा, तीसरा भाषण में यदि वोटो की राजनीति से प्रेरित हुआ तो भी न भी हुआ दोनों ही परिस्थितियों में मुश्किल होगा, जिसकी गूंज सीधी बजट सत्र में विपक्ष को हल्ला मचाने का मौका देगी जो आने वाले लोकसभा चुनाव में कष्टप्रद हो सकता है। भविष्य में चुनाव में सीधे हार का कारण भी बन सकता है, इसलिए बेहतर है कि सरदार मनमोहन की आड़ में सप्ताह भर के प्रधानमंत्री पद को ही अस्पताल में बाईपास के लिए भेज दो, ताकि सारी झंझटों की अस्पताल में मरहम पट्टी भी हो जाएगी और पक्ष-विपक्ष को कोई मौका भी नहीं मिलेगा।

शेष पेज 2 पर

साप्ताहिक
समय माया

संपादकीय

भ्रष्ट गणों का निकृष्ट तंत्र

कानून का पालन करवाने वाले खुद कानून से ऊपर

राष्ट्र में आजादी के 58 वर्ष बाद और गणतंत्र बनने 50 वर्ष जनता को सत्ताधीशों की कार्य शैली, जनधन के खर्चे का हिसाब जानने के लिए सूचना का अधिकार अधि. 05 लागू किया गया, वैसे म.प्र. में यह कानून सन 1998 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह ने यह कानून पूरे देश में सबसे पहले लागू कर दिया था, जो घोर भ्रष्ट होने के बाद भी धन्यवाद के पात्र हैं।

कानून का पालन करवाने वाले न्याय की शीर्ष सत्ता पर बैठने वालों को जनता के धन से वेतन व अन्य सुविधाएं मिलती हैं, उन्हें राष्ट्र के संविधान और कानूनों का स्वयं पालन करने और सत्ताधीशों को पालन करवाने की न केवल दायित्व वरन् राष्ट्र को संचालित करने, जनता का कानून में विश्वास बनाए रखने की भी जिम्मेदारी है। पर न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के हो या वहां से चलकर जिलों और तहसीलों में बैठे सत्र न्यायाधीश तक अपने आपको इन कानूनों से ऊपर खुदा मान बैठते हैं और खुले में न्याय के नाम पर खुली वसूली करते हुए धज्जियां उड़ाते रहते हैं। सच्चे अर्थों में हमारे देश की भ्रष्ट न्याय पालिका हो भ्रष्टगणों को पालती है और भ्रष्टाचार करने वालों को प्राश्रय देती है। यदि हमारी न्यायपालिका में भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए तो राष्ट्र का आधा भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए। फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश क्या सूचना अधिकार कानून से ऊपर हो गए जो अपनी सम्पत्ति घोषित नहीं करेंगे, जबकि न्याय पालिका में जनता का विश्वास बना रहे इसके लिए सबसे पहले न केवल स्वयं सम्पत्ति घोषित करना चाहिए, वरन मंत्रियों और संत्रियों को स्वयं की सम्पत्ति घोषित करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने यह कहकर कि वो इस कानून से ऊपर हैं वो सम्पत्ति घोषित करने के लिए बाध्य नहीं है। राष्ट्र की लोकातांत्रिक शासन प्रणाली की धज्जियां बिखेर दी हैं। जनता का न्याय पालिका से न केवल विश्वास तोड़ा, वरन् अपने चरित्र और कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह लगा दिया आखिर कानून के सर्वोच्च पद पर बैठने वालों को कानून का पालन क्यों नहीं करना, यदि उन्हें सर्वोच्च पद पर बैठकर कानून का पालन नहीं करता तो राष्ट्र की जनता को भी उनके श्रीमुख से निकाले कानूनों का पालन क्यों नहीं करना?

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ये वक्तव्य ही उनके भ्रष्टाचार में आकंठ लिप्त होने का पर्याप्त सबूत है। फिर प्रधानमंत्री कार्यालय जो भ्रष्टाचार का राष्ट्र का प्रमुख केंद्र है ने उनकी और उनके मंत्रियों को सूचना कानून में सम्पत्ति का ब्यौरा देने से मना कर सिद्ध कर दिया कि वो भी घोर भ्रष्टाचारी है, जिसे जन ने चुनकर भेजा है, यदि सम्पत्ति का ब्यौरा देने से मना कर दिया है तो फिर किसी भी शासकीय कार्यालय में बैठे अधिकारियों से न केवल सम्पत्ति की जानकारी मांगना या सूचना अधिकार में जानकारी वो भी क्यों देंगे, पने ही उन्हें बैठाया है वो जो कर रहे हैं काला-पीला आपके कहने पर कर रहे हैं क्यों देंगे वो जानकारी?

जब न्यायापालिका के न्यायाधीश ही पारदर्शी नहीं होंगे तो दूसरे सत्ता में बैठेगणों से पारदर्शिता लिए कोई भी न्यायालय कैसे उम्मीद कर सकता है, कैसे लिखित निर्देश दे सकता है या उनके भ्रष्टाचार पर कैसे अंगुली उठा सकता है। न्यायाधीश कोई खुदा नहीं, विधिवत कानून के अंतर्गत नियुक्ति हुई है, कानून के अंतर्गत जनता के धन से उन्हें वेतन मिलता है, कानून के अंतर्गत विधिसम्मत कार्य करने के लिए सबसे पहले उन्हें कानून को शिरोधार्य कर पालन कर पारदर्शिता के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध करवा कर जनता का कानून में विश्वास बनाए रखना चाहिए।

3 माह ...

पेज 6 से जारी

और अपनी बैंक खातों की ही प्यास बुझा पाएंगे बेचारे।

- रुपए 427 करोड़-सूखा व आपदा के लिए- इस पैसे का पूरा सदुपयोग सूखे व आपदा वाले जिलों के जिलाधीश और जिला पंचायत अधिकारी अपनी जेबों को सूखे और आपदा का प्रबंधन में करेंगे और सीधा पैसा उस जिले के मंत्री और लोकसभा प्रत्याशी के चुनाव प्रबंधन में भी काम आएगा, पुराने विधानसभा के चुनावों में दिए गए चंदे का प्रबंधन भी अधिकारी, कर्मचारियों के माध्यम से नेता विधायक भी कर लेंगे।

रुपए 280 करोड़ जल संसाधन को- म.प्र. जल संसाधन विभाग बनाम धन संसाधन विभाग का ये अनुपूरक बजट भी मंत्री, संत्री और यंत्रियों के साथ कर्मीयों के 3 माह के बजट को ही सींचेगा, यहां पर जो बजट/प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं तो डेढ़ से दुगुने ही बनाए जाते हैं, ताकि सबके बैंकों में भी धन के बांध बंधे रहे ये होगा अनुपूरक बजट का भविष्य।

लूट सके ...

पेज 5 से जारी

घरों में रुके रहते हैं, वो न तो यहां काम मिल रहा है, दूसरी और वो इस चक्कर में बाहर निकलकर भी मजदूरी रोजगार करने नहीं जा पाते हैं। वो बाहर का रोजगार भी हाथों से जार रहा है इस प्रकार ये रोजगार छीनने व धन डकारने की गारंटी योजना बन चुकी है।

यह बात भाजपा संगठन मंत्री नरेंद्र तोमर भी जानता था, इसलिए चंबल के भ्रष्ट कार्यपालन यंत्रियों के रूप में खरगोन में जादौन जिसके बनाए 2006 के तालाबों में कई फूटे जो कि 4 वर्षों से बैठकर भारी भ्रष्टाचार कर रहा है, वही हाल बड़वानी, म.प्र. जल संसाधन विभाग का उपसंभाग अधिकारी पिछले 4वर्षों से ज्यादा समय से प्रभारी कार्यपालन अभियंता बना बैठा है ये आर.एस. राठौर अपने आप को भाजपाई तोमर का रिश्तेदार बताकर भारी लूटपाट कर रहा है, वही हाल झाबुआ में बैठे तोमर का है। खंडवा में बैठे का.यं. शब्बीर खान और बुरहानपुर में बैठो का.यं. एच. खान भी दोनों हाथों से बटोरने में लगे हैं। ये अपनी जाति वालों पर विशेष रहम रखते हैं।

समय माया ने बड़वानी के राठौर, धार के बड़कुल, खरगोन के जाधव, खंडवा के खान की शिकायत चुनाव आयोग को भी भेजी थी, जिस पर कार्यवाही का इंतजार है।

पूर्व नियोजित ...

पेज 1 से जारी

यदि सरदार मनमोहन की बाईपास होना भी थी तो ये मामला तत्काल तो निर्णित नहीं होता। 6-8 महीने पहले से ही गुणदोष नजर आने लगते हैं, जनवरी की ठंड में बाईपास करवानी भी थी तो दिसम्बर-जनवरी के अंतिम या पहले सप्ताह में भी मनमोहन की बाईपास की या करवाई जा सकती थी। परंतु जालसाज कांग्रेसी गिरोह को मनमोहन की बाईपास की या करवाई जा सकती थी, परंतु जालसाज कांग्रेसी गिरोह को मनमोहन की बाईपास नहीं करनी या करवानी थी। इन धूर्त जालसाजों को तो मात्र वास्ता था तो गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री के लालकिले की प्राचीर से दिए जाने वाले भाषण को ही भर बाईपास करना जो इसप्रकार स.मन मोहन को एम्स में हास्पिटलाइज्ड करके कर दिया गया, क्योंकि वह भाषण पूरी दुनिया में प्रसारित होता।

उधर दक्षिण में श्रीलंका सरकार तमिल टाईगरों के हर अड्डे पर लगातार वायु, जल और थल से पिछले चार महीने सेहमले कर हजारों तमिल स्वतंत्रता वादी चीनों को मार चुकी है, उत्तरी-पूर्वी मालादिव, शहर पर श्रीलंका की फौजों का कब्जा हो चुका है, सवा दो लाख की आबादी में बच्चे वयस्क और बूढ़ोंकी जिदगी गोलियों की सायं-सायं में गुजर रही है, तमिल मुख्यमंत्री केंद्र से कई बार गुहार लगा चुके हैं। उन्हें बचाने और युद्ध विराम की परंतु भारत सरकार का प्रधानमंत्री तो हास्पिटलाइज्ड पड़ा है, 26 जनवरी को इस पर भी टिप्पणी करना आवश्यक थी, पर अस्पताल में सरकार की बाईपास की इस पर टिप्पणी करने से बच गया। फिर कांग्रेस द्वारा पाले गए और संरक्षित आतंकवाद के ऊपर क्या बोले जो उसके गले की फांस बन गया। दुनिया को दिखाने के लिए दोनों देशों के सत्ताधीश जो नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं या लडकर दिखा रहे हैं। उसका तमाशा तो पूरी दुनिया मीडिया के मुद्रित समाचार पत्रों और दृश्यों, टी.वी. चैनल्स पर देखने, सुनने और पढ़ने को मिल ही रहा है, होना जाना कुछ भी नहीं है। समय के साथ सब ठंडा हो जाने वाली यह नौटंकी कुछ समय बाद फाइलों में बंद होकर रह जाएगी।

जालसाज...

पेज 8 से जारी

के भ्रष्ट सचिवों, अधिकारियों से घिरा है कि सलाह पर इन भ्रष्ट सेवानिवृत्ति प्राप्त इँडियन एव्यूसिंग सर्विस के मुख्य सूचना आयुक्त पी.पी. तिवारी और इकबाल अहमद और इंडियन (क्राइम प्रोटेक्शन) सर्विस के आयुक्त दिनेश जुगरान की जो नियुक्ति की जबकि इनके भ्रष्टाचार के पूर्व से ही सत्ताकाल के सैकड़ों प्रकरण थे, नियुक्त ही इसलिए किया कि वो पारदर्शिता के नाम पर स्वयं घोर अपारदर्शी व्यवहार कर सूचना के अधिकार अधिनियम 05 की धज्जियां उधेडते रहें।

दूसरा आखिर ये सारे आयुक्त इकबाल अहमद, दिनेश जुगरान और पीपी तिवारी ने सत्ता में बैठकर तो जिंदगी भर लूटपाट की ही थी, सेवा निवृत्ति के बाद इन्हें ईश्वर ने कुछ अच्छा ईमानदारी से राष्ट्रहित करने और भ्रष्टाचार दूर करने का मौका भी दिया तो भी जीवन भर जो गंदगी इनके मस्तिष्क और शरीर के रक्त के कतरे-कतरे में भर गई है वो जीवन के अंतकाल में कैसेत्याग सकते हैं। तो इ हरामखोरों से ईमानदारी की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

अभी हाल ही में एक निर्णय आयुक्त दिनेश जुगरान ने 15.1.09 को दिया, जिसमे जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल की अपील को भी निरस्त कर दिया, जबकि उक्त प्रतिप्रार्थी सूचना के अधिकार को बलाए ताक रखकर न केवल जानकारियां नहीं दी वरन् उसने पने आप को खुदा मानते हुए अपनी ही बात कहकर कि आवेदन में स्टाम्प नहीं लगे थे, जबकि आवेदक श्री अजमेरा रुपए 10 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर ही जानकारी मांगी थी। उल्टे ही जानकारी दिलवाने की अपेक्षा न्यायालयों में फैले भ्रष्टाचार की नींव पुख्ता की।

अगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचमुच ईमानदार थे तो सूचना के अधिकार अधि. 05 को भी वैसे ही शिरोधार्य करते जैसे अन्य कानूनों के अंतर्गत उन्हें नियुक्ति मिली, कानूनों के अंतर्गत काम जनता के धन से उन्हें वेतन मिलता है। इसके विपरीत आयुक्त दिनेश जुगरान ने न्यायाधीश के अनुसार 1961 के कानून को ते माना पर सू.आ. 05 को भूलकर अपील को नस्तीबद्ध कर दिया, ये हैं इनकी ईमानदारी और पारदर्शिता की सच्चाई।

लोकायुक्त और आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो को इनकी शिकायत की जाएगी कि आखिर ये सूचना आयोग के भ्रष्ट किस प्रकार भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे हैं, नहीं तो इन हरामखोरों को उच्च न्यायालय में बुलाया जाएगा।

बिजली बेच...

पेज 8 से जारी

की कीमत थी, मात्र 35.57 करोड़ रुपए जल विद्युत के 290.53 मे.वा. कि कीमत थी मात्र 3.37 करोड़, केंद्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत की 1920.20 मे.वा. की कीमत थी मात्र 42.13 करोड़, केंद्रीय क्षेत्र राष्ट्रीय विद्युत निगम के 117.94 मे.वा. की कीमत थी मात्र 3.28 करोड़, डी.व्ही.सी. ई.आर. के 70.81 मे.वा. की कीमत थी रुपए 1.77 करोड़, इंदिरा सागर के एनएचडीसी के 273.80 मेवा की रुपए 5.39 करोड़, ओंकारेश्वर के 130.21. मेवा की रुपए 2.73 करोड़, सरदार सरोवर के 109.84 मेवा की रुपए 1.18 करोड़ रुपए कुल 5120.79 मेवा की मासिक कीमत भुगतान रुपए 97.65 करोड़ था, ये सारे समंक विद्युत मंडल की साइटों से ही प्राप्त किए गए।

अब प्रश्न यह उठता है कि अकेले इंदौर से रुपए 300 करोड़ से ज्यादा का राजस्व कमाने वाले विद्युत मंडल अपने उपभोक्ताओं के लिए न तो बिजली खरीदकर आपूर्ति कर पा रहा है, न ही ये इसमें प्रबंध संचालक बन बैठे धूर्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के अधिकारी मंडल के ही यंत्रीयों, अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर वेतन दे पा रहे हैं। साथ ही ईमानदारों को जो कि पूरा इनकी 40 प्रतिशत ज्यादा लूट के बाद भी बिल भर रहे हैं बदले में घरों में ही नहीं वरन् उद्योग धंधों और कारोबारों को भी अंधेरा वोट कर जिंदगी में पूर्ण अंधेरा कर रहे हैं, जबकि किराया पूरा 24 घंटे का वसूल रहे हैं। कहीं 10 घंटे, कहीं 12 घंटे, कहीं 14 घंटे, 18 घंटे बिजली देकर जानबूझकर परेशान कर रहे हैं।

चुप है..

पेज 1 से जारी

हवाई हमलों तक से हत्या की गई बाद में बदले में उसी लिट्टे ने राजीव की दक्षिण में मानव बम के साथ हत्या कर दी गई।

लिट्टे की स्थापना के उद्देश्य के अनुकूल वे अभी भी श्रीलंका में अपना स्वतंत्र राष्ट्र का अस्तित्व चाहते हैं। भारत के दक्षिणी राज्यों, तमिलनाडु, केरल आदि से वहां की जनता कई पीढ़ियों से श्रीलंका में न केवल आते-जाते रहे हैं, वरन् स्थाई वासी भी रहे हैं। उत्तरी-पूर्वी श्रीलंका में उनका वर्चस्व रहा है। श्रीलंका में प्रधानमंत्री राजपक्षे के सत्ता संभालते ही उन्होंने तमिलों के और लिट्टे के गढ़ मोलापटिबू शहर पर कब्जा कर लिया है।

सी.एन.एन. के अनुसार लिट्टे का मोलायटिबू में मिलिट्री हेड क्वार्टर था, जिसमें लाखों नागरिक गोलियों और बमों की बौछारों में फंसे हुए हैं और दसियों हजार घायल भी हो चुके हैं, जिसमें नवजात शिशुओं से लेकर वयस्कों और बूढ़े भी हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री करुणानिधी ने जो कि केंद्र की सत्ता का घटक दल भी है सरकार से मांग की थी कि श्रीलंका में तमिलों के संहार को रोका जाए, यदि उस पर प्रधानमंत्री ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो वो सत्ता और सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे। इसके विपरीत कांग्रेसी मक्कारों ने, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल है न तो उनके हित में मुंह खोला और उल्टे ही बेचारा 120 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री का एक सप्ताह का अस्पतालीकरण कर तीन सप्ताह के लिए सरकार को बिस्तर पर ला पटका। सी.एन.एन. के अनुसार 1983 से 70000 हजार तमिल श्रीलंका में सेनाओं द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए हैं जो वास्तविकता में 7 लाख होंगे।

आवश्यकता..

पेज 1 से जारी

परिवर्तन होने वाला नहीं। दूसरा अमेरिका की राजनीति में राष्ट्रपति ओबामा हो या बुश वहां का राष्ट्रपति भी भारत के प्रधानमंत्रियों की तरह ही वहां मुखैरा भी होता तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों, हथियार उत्पादकों, पूंजीपतियों की कठपंतली ही है। जैसा कि भारत में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी भी दल-दल का हो होता तो आखिर अंबानी, टाटा, बिरला जैसे धूर्त जालसाजों की कठपुतली ही है।

अर्थात अमेरिकी हथियार निर्माता राष्ट्रपति के माध्यम से चुनाव जीतने के लिए मोटा चंदा देती है। पाकिस्तान को वित्तीय, सामरिक सहायता देकर चाहते हैं कि वहां पर आतंकवाद की फसलें शातिर से शातिर आतंकवादी बनाए। पूरे भारत में तांडव बरपाए। उसके बाद इस 120 करोड़ की आबादी का गुलाम मानसिकता का प्रधानमंत्री, आतंकी हमले होने की दशा में उनके सामने गिड़गिड़ाए, ज्यादा हो-हल्ला मचे तो सीमाओं पर अपनी बहादूरी दिखाने, सेनाओं को पहुंचाए, दूर खड़े रहकर एक दूसरों पर मात्र चीखना-चिल्लाने और गालियां बरसाएं।

वैसे भारत हो अमेरिका हो, इंग्लैंड, जर्मनी या जापान सत्ता किसी भी पार्टी की हो नेता कोई भी सत्तायें पूंजीपतियों की कठपुतली बन ही नाचती है। उनके हिसाब से उनके हित साधने में उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए जाते हैं, बने हुए कानून बदले जाते हैं।

राहुल..

पेज 1 से जारी

मुस्लिमों, पिछड़ा वर्ग, आदिवासी, हरिजनों के वोटाकर्षण पर कुछ तो षडंयत्रयुक्त वक्तव्य देते।

इसके विपरीत प्रधानमंत्री की बाइपास के बहाने अगर दुनिया से ही पास हो जाते या कर दिये जाते तो आने वाले लोकसभा चुनाव तक राहुल को प्रधानंत्री की शपथ दिलवा कर 26 जनवरी 09 देश की शान लालकिले पर राहुल चूजे से कुछ भी घोषणा करवाकर, ताकि जातिवादी संघर्ष, पाकिस्तान से युद्ध जैसी कुछ टांय-टायं, बम धमाके, युद्धक विमानों की गर्जना, खून-खराबा, जलयुद्ध जैसा कुछ जोश मरने वाला कारनामा कर राहुल को युवा हृदय सम्राट घोषित कर महानायक बनाने का षडयंत्र किाय जाता, कांग्रेस में यह कार्य दिल्ली में नियोजित किया गया था, जिसमें इटली के पोपका भी वरदहस्त था, सोनिया का प्रधानमंत्री न बन पाने के कारण इटली का पोप नहीं कर पाया वो राहुल को प्रधानमंत्री के ह्रप में स्थापित करके किया जायेगा। जिस दिन भी भविष्य में राहुल को प्रधानमंत्री बनाया गया भारत के कांग्रेसियों से ज्यादा पोप को होगी, और बाकायदा उसे दुनिया देखेंगी।

यही कारण है कि कांग्रेसियों ने चावला के इतने भ्रष्टाचार के बाद भी मुख्यचुनाव आयुक्त बना दिया जाएगा, कई चरणो में चुनाव होने का मतलब है कांग्रेस के लिए सारे नियम कानून ताक पर रखकर उनके पक्ष में भारी वैध-अवैध वोटिंग करवाना ही रहेगा, अब चूंकि प्रधानमंत्री बिस्तर पर है अर्थात् भारत की सारी व्यवस्थाओं का प्रशासन का बाईपास करके प्रणव मुखर्जी को सौंप दिया गया है। जितने दिन राष्ट्र का प्रधामंत्री बिस्तर पर है उतने दिन जो काला-पीला कांग्रेस धन कमाने, कमीशन खाने, चुनाव की गोटियां जमाने में किया जा सकेगा, किया जाएगा और जा रहा है।

न.घा. भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में नया कारनामा

महाभ्रष्ट धूर्त, इंगले, सनावद मुख्य अभियंता

ठेकेदारों को अरबों अग्रिम, डूबंत

भ्रष्ट बयानी, कर्णसिंग को पुनः ठेका
दोनों ठेकेदारों ने पुराने ठेके पूरे नहीं किए,
इंगले, ठेकेदार की कठपुतली, नर्मदा-क्षिप्रा लिंक
रुपए 4590 करोड़ केवल डकारेंगे

भोपाल। नघा विप्रा विकास के नाम पर केवल वैधानिक लूटपाट, भ्रष्टाचार और जालसाजी से धन डकारने का विभाग बन गया है। यहां बैठा तकनीकी सदस्य भाटिया जबलपुर न.घा. वि. प्राधिकरण के जबलपुर अंचल का ऊपरी परियोजना का मुख्य अभियंता भी है। इस भ्रष्ट को आखिर एक साथ दोनों पदों पर मात्र कागजी कार्यवाहियों में जालसाजीपूर्ण आंकडे भर लूटपाट और भ्रष्टाचार से धन डकारने के लिए ही बैठाया गया है।

आई.एस. व इंजीनियर पर असुरों की आसुरी भ्रष्टाचार पूर्ण मानसिकता से घिर कर मुख्यमंत्री शिवराज जो न.घा.वि.प्रा. का अध्यक्ष और मंत्री भी है इ असुरों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के तांडव में मस्त हो परियोजना नहरों के निर्माण और सिंचाई से दूर वसूली के नृत्य में लीन है। यही कारण था कि चुनाव से पूर्व 2280 करोड़ के ठेकों की निविदाएं बुलाकर ताबड़तोड़ निपटारा कर अधिकांश निविदाएं उन्हीं भ्रष्ट ठेकेदारों बिहानी और कर्णसिंग जो सोम का साझेदार है को न केवल पुनः दे दी गई जबकि इन दोनों हरामखोर जालसाजों ने न तो पूर्व के किसी ठेकों के कार्यों को पूरा किया था न उनकी गुणवत्ता थी इसके विपरीत लगातार समय माया के प्रकाशनों के व अन्य शिकायतों के चलते मुख्य सतर्कता तकनीकी अधिकारी आए और वसूली कर चले गए, फिर भी उन्हें न केवल ठेके दिए गए वरन् उन हरामखोरों को बिना 14प्रतिशत का 10 प्रतिशत अग्रिम कार्य शुह्व करने के लिए और 5प्रतिशत अग्रिम कार्यशाल पूंजी के लिए भी दे दिया गया, जिसे दोनों ही ठेकेदार डकार कर चुपचाप बैठ गए। यह रुपए 385 करोड़ का अग्रिम जिसमें चुनाव के पूर्व शिव, असुरों के प्रिय ने भी चुनाव के लिए कमीशन के ह्वप में डकार कर हजम कर गए इसलिए ये भांग रमाए मस्त बैठे हैं।

जबकि रुपए 17 करोड़ के टर्न की ओंकारेश्वर की बायीं तट नहर को नवम्बर 08 में पूरा हो जाना था और नहर के किनारे के किसानों को 2009 की रबी की फसलों को पानी सिंचाई के लिए मिलना चाहिए था। ये ठेका भी सोम कंस्ट्रक्शन के साझेदार कर्णसिंग के पास था, साथ ही इसमें ठेके से 5वर्ष, जिसमें 2 वर्ष निर्माण के और 3 वर्ष रखरखाव के थे इसके कार्यपालन अभियंता धूर्त इंगले था, जिसे इस आरोप से बचाने पहले अधीक्षण यंत्री का प्रभार देकर बाद में पदोन्नत कर दिया गया, ताकि इंदिरा सागर नहरों के मुख्य अभियंता के 31 जनवरी 09 को सेवानिवृत्ति के साथ पूरे 10 संभागों को इसे मुख्य अभियंता का प्रभारी बनाया जा सके। चूंकि ये महाभ्रष्ट जालसाज ठेकेदारों की कठपुतली बन उन्हें धड़ल्ले से भुगतान करवा कर स्वयं भी करोड़ों रुपए डकारता है और भोपाल में बैठे नर्मदाघाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में बैठे सदस्यों से लेकर अध्यक्ष शिव तक भी धन पहुंचाता है। ओंकारेश्वर की बायीं तट नहर का नवम्बर 08 में जो कार्य पूरा होना था उसका मात्र 45-48 प्रतिशत ही काम पूरा हुआ है, इसकी गारंटी/वारंटी समय 5वर्ष में भी यह कार्य पूरा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इन नहरों के निर्माण में हर स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, जहां भराई में काली मिट्टी ही भरी गई, वहीं खुदाई में मिट्टी, मुरम में कठोर चट्टानों की खुदाई के बिलों का भुगतान किया गया, जहां क्रांकीट की गई उसमें भी 10 से.मी. की जगह मात्र 7-8 से.मी. मोटी परत डाली गई। दूसरी तरफ सीमेंट का प्रतिशत भी मात्र 10 से 15 प्रतिशत ही रखा गया। उन नहरों में पानी भरने से पूर्व ही तल और ढाल चटक गई। साथ भराई और खुदाई में मानक स्तर के वर्म नहीं बनाए गए, जिससे दोनों तरफ से गिरने वाली मिट्टी, पत्थर, सीधे नहर के तल पर पहुंचकर पानी के बहाव में बाधक बनेंगे। साथ केंद्रीय जल आयोग के डिजाइन्स और ड्राईंग्स के स्वीकृत नक्शों के हिसाब से काम करने की अपेक्षा इस हरामखोर इंगले ने खुलकर ठेकेदार को मनमर्जी करने की छूट दे दी। मात्र धान के बदले में इतनी सारी अनियमितताओं के बाद भी सदस्य तकनीकी भाटिया व अन्य सदस्यों के साथ सचिव प्रदीप भार्गव, अध्यक्ष मु.मं. शिव ने उसे न.घा.वि.प्रा. के सनावद जैसे न.घा.वि.प्रा. अंचल का मुख्य अभियंता का प्रभार मात्र इसलिए ही सौंप दिया ताकि वह लूटपाट करे और चढोत्रा चढ़ाए, जबकि इंगले ने म.प्र. जल संसाधन विभाग में रतलाम में का.अ. के पद पर रहकर वहां के कर्मचारियों की भविष्यनिधि डकार ली थी।

जिस नर्मदा क्षिप्रा लिंक की बात और सर्वे की तैयारी चल रही है इस योजना की लागत रुपए 4590 करोड़ होगी, केवल धन डकारने की ही तैयारी है, क्योंकि नर्मदा को 110 से 130 फीट समुद्र तल की ऊंचाई से क्षिप्रा से 480 फीट समुद्र तल की ऊंचाई पर लाने और कम से कम 100 कि.मी. तक पाईप लाइन या नहरों से पानी लाने के लिए 100 मे.वा. बिजली हर दिन चाहिए तो कहां से और कब तक आएगी, फिर उसकी हर महीने बिजली बिल की राशि का क्या होगा, यह योजना भी सफेद हाथी हो जाएगी, फिर मंत्री, नेता इंजीनियर उसकी बड़ी-बड़ी मोटरें बेच कर खा जाएंगे जैसा कि संभाग क्रमांक 19 के कुक्षी तहसील जिला खरगोन में कठोर प्रोजेक्ट का हाल हो रहा है। प्रदेश में कोई भी लिफ्ट इरीगेशन कुभी सफल नहीं हो सका, यही कारण था कि पेशे से इंजीनियर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह ने म.प्र. जलसंसाधन अंतर्गत कार्य कर रहे म.प्र. लिफ्ट इरीगेशन लि. को आते ही भंग कर दिया था। इस दृष्टिकोण से नर्मदा, क्षिप्रा लिंग परियोजना भी विद्युत के अभाव में न केवल ठप्प हो जाएगी, वरन् केवल लूटपाट और कागजी सफेद हाथी की आड़ में नीचे से ऊपर तक धन डकारने का साधना सिद्ध होगी। नर्मदा क्षिप्रा के स्थान पर चंबल का पानी व अन्य छोटी नदी नालों को पानी जो 480 फीट से समुद्र चल से ऊंचाई पर बहते हैं का जल 460 फीट की ऊंचाई पर त्वरण वेग से मोड़ कर मिलाकर भरा जा सकता है। साथ ही क्षिप्रा का यदि 10 फीट गहराई बढ़ा दी जाए तो भी वर्षभर जल मिल सकता है, क्षिप्रा में भविष्य में अभी नहीं तो 10 वर्ष बाद काम इसी योजना पर करना पड़ेगा।

जहरीले है जेनेटिक मोडीफाइड बीज की फसलें

यूरोपीय देशों जीएम फसलों का भारी विरोध

नई दिल्ली। बीटी बैंगन एक जीएम या जिनेटिकल मॉडिफाइड फसल है। यानी जिसके जीन में फेरबदल की गई है चूंकि इसमें एक बैक्टीरिया बेसिलस थूरिनजेनेसिस (बीटी) के एक जीन को डाला गया है, इसलिए बैंगन की इस नस्ल का नाम बीटी बैंगन। इसे डिवेलप करने वाली कंपनी है मॉनसेंटो।

भारत में माहिको मॉनसेंटो की प्रतिनिधि कंपनी है। मॉनसेंटो की दलील है कि बीटी बैंगन में मौजूद जीन फल और तने को छेदने वाले कीड़े को नाकाम कर देगा। वह कीड़े के पाचन तंत्र को बेकार कर देगा और कीड़ा मर जाएगा।

अपनी इस दलील के समर्थन में कंपनी ने कुछ आंकडे देकर यह बताने की कोशिश की है कि इससे हानिकारक कीटनाशकों का कम से कम प्रयोग होगा, किसानों की आमदनी बढ़ेगी वगैरह।

भारत में ऐसी फसलों पर निगरानी रखने वाली एजेंसी जिनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल (जीईएससी) ने देश में पहली बार बीटी बैंगन के बड़े स्तर पर फील्ड ट्रायल की मंजूदी दे दी। इस बीच ग्रीन पीस जैसे संगठनों के भारी विरोध और एक फ्रेंच वैज्ञानिक की रिपोर्ट ने बीटी बैंगन के उस खतरनाक पहलू को उजागर किया जो सामने आने ही नहीं दिया गया था। यूरोप के देशों में जीएम फसलों का भारी विरोध किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जिन जानवरों पर इसका टेस्ट किया गया, उनमें खून जमने की स्वाभाविक प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ा। फिलहाल 14 जनवरी को जीईएस की बैठक में फैसला लिया गया कि फ्रेंच रिपोर्ट में उठाए गए सवालों पर विचार किया जाएगा।

इस सिलसिले में कोएलिश फॉर जीएम फ्री इंडिया के कोआर्डिनेटर और फूल पालिसी एनालिस्ट देवेंद्र शर्मा कई सवाल उठाते हैं, वह पूछते हैं देश में बैंगन की कोई क्राइसिस नहीं है, न ही यह कोई बड़ी फसल है, फिर बीटी बैंगन की क्या जरूरत? क्या गारंटी है कि बैंगन में मौजूद यह जीन इंसान के जीन में नुकसानदायक बदलाव पैदा नहीं करेगा? इस बैंगन और साधारण बैंगन की शक्ल में कोई फर्क नहीं है, फिर इसे न खाने वाले भेद कैसे करेंगे?

बीटी कॉटन ने जो दावे किए थे वे सही साबित नहीं हुए। उसके इस्तेमाल के बाद भी कपास का नुकसान और किसानों की आत्महत्या जारी है। ऐसे में बैंगन जैसी आमसब्जी को अनजान जहरीले असर वाली सब्जी में बदलना कहां की समझदारी है।

ग्राम पंचायत सात्याचासियों
की ओर से
राष्ट्र के नववर्ष एवं गणतंत्र
दिवस की शुभकामनाएं
श्रीमती श्याम यादव, (अध्यक्ष)
उपाध्यक्ष (नगर पंचायत नया हरसूद)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी (नगर पंचायत नया हरसूद)

ग्राम पंचायत फेफरी सरकार
जिला खंडवावासियों को
राष्ट्रवासियों को गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं
लखन लाल सोलंकी (सचिव)
श्री कृष्णा (सरपंच)
समस्त पंचगण
ग्राम पंचायत फेफरी सरकार

साप्ताहिक
समय माया

33 अधिकारियों के विरुद्ध जांच

सेवानिवृत्ति, मृत्यु के बाद भी चलती रहती है, जांच का ढकोसला

लोकायुक्त की जालजासियों के विरुद्ध भी कसना होगा शिकंजा

भोपाल। भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध शिकंजा कसने के लिए लोकायुक्त संगठन की स्थापना की गई थी तब से अभी तक कई जांचे लंबित है, चल रही हैं। सेवा निवृतति के बाद तक चलती रहंगी और मृत्यु के अंतिम सत्य के साथ नष्ट हो जाएगी यहां सैकड़ों जांचों में जो कि 83-84 से लंबित है, अधिकारी स्वर्ग सीधार गए पर इन जालसाजों की जांचे पूरी नहीं हुई। सैकड़ों सेवानिवृत्त हो चुके हैं। विडंबना यह है कि लोकायुक्त की जांचों पर भी भ्रष्टाचार का गहरा साया है, लोकायुक्त संगठन के कार्यों को भी नियमित और शीघ्रता से पूरा करने के लिए किसी गैरशासकीय संगठन के ही उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करना पड़ेगी।

इसके विपरीत यह कटु सत्य भी हमें स्वीकार करना ही पड़ता है कि लोकायुक्त संगठन चूंकि शासकीय मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों के विरुद्ध की जांच करता है, इसलिए इन्हें पर्याप्त अधिकारी, स्टाफ, वकीलों, वाहनों व अन्य संसाधनों की आवश्यकता पूरी नहीं की जा रही है, वर्षों से जबकि प्रकरणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, स्वाभाविक है उस अनुपात में अधिकारी कर्मचारी और संसाधन भी सरकार को इन्हें उपलब्ध करवाना चाहिए, फिर जहां सत्ता की शक्ति सम्पन्नता होगी, वहां उसका दुरुपयोग होगा ही, धन वसूला ही जाएगा,यह शक्ति के प्रादुर्भाव से ही प्रारंभ हो गया था, जो मानव सत्यता के साथ ही उतनी तेजी से ही विकसित और स्थापित होता गया। इन तथ्यों को नजर अंदाज भी कर दें तो भी सबकी अपनी उपयोगिता तो है ही।

हाल ही में लोकायुक्त संगठन ने जिन भ्रष्टों के खिलाफ जांच शुरु की है उनकी सूची निम्नानुसार है-

उपरोक्त अधिकारियों को जिन मामलों में जांचे शुह्व की गई है ये उनके वास्तविक भ्रष्टाचारों का तिनका मात्र है, जबकि इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी अर्थात आईएएस, इंडियन (क्राइम) प्रोटेक्शन, सर्विस अर्थात आईपीएस और इंडियन फारेस्ट (ईटिंग) सर्विसेज हर दिन किसी न किसी बड़े भ्रष्टाचार के अंजाम देते ही हैं। जानबूझकर, धन, शक्ति पद के आधार पर या अंजाने में फिर भी लोकायुक्त की जांच से कहीं न कहीं तो भय पैदा होता ही है।

लोकायुक्त संगठन द्वारा प्रदेश के 33 नौकरशाहों द्वारा किए गए घपलों-घोटालों की जांच की जा रही है। प्रमुख सचिव से लेकर कलेक्टर के पद पर आसीन इन अधिकारियों के खिलाफ तरह-तरह के आरोप लगे हैं। लोकायुक्त की जांच के घेरे में सबसे ज्यादा 23 आईएएस अधिकारी है एवं सबसे कम 3 आीएफएस अधिकारी शामिल हैं, जबकि आईपीएस अफसर 7 हैं।

लोकायुक्त संगठन को सबसे ज्यादा शिकायतें इंदौर जिले में पदस्थरहे अधिकारियों की मिली है। आईएएस अधिकारियों के साथ आईएएस अधिकारी भी इंदौर में पदस्थापना के दौरान व भ्रष्टाचार करने के बाबद है। एक आईएफएस अधिकारी पर मोरों के दाना-पानी डकार जाने का आरोप लगा है।

रिटायर भी हो चुके अधिकारी- लोकायुक्त जांच के घेरे में आए एक आईएएस अधिकारी रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन उनकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। अधिकारी एसएस उप्पल हैं, जबकि एम.ए. खान भी इसीसाल मार्च में रिटायर हो जाएंगे।

एक अधिकारी छत्तीसगढ़ पहुंचा- लोकायुक्त संगठन की जांच के दौरान एक अधिकारी टी.राधाकृष्णन को छत्तीसगढ़ राज्य आवंटन हो जाने के कारण वहां चले गए। उनकी जांच अभी तक चल रही है।

आईएएस अधिकारी- इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी जिन पर जांच चल रही है

नाम	इस पर रहते लगा आरोप	जांच का विषय	जांच की स्थिति
पदमवीर सिंह	प्रमुख सचिव लोकनिर्माण	विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप पत्र जारी नहीं करके अवैध व गलत पदोन्नति दिलवाकर पद का दुरुपयोग किया	जांच चल रही है
जेएन कंसोटिया	कलेक्टर राजगढ़	एक सरपंच के खिलाफ प्रकरण में छल से मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हुए शासन को झूठी रिपोर्ट देना	जांच चल रही है
मनीष श्रीवास्तव	कलेक्टर शिवपुरी	त्रैमासिक-अर्द्धवाषिक परीक्षा के मुद्रण कार्य में घोटाला	जांच चल रही है
अरुण कुमार पांडे	कलेक्टर रायसेन	गौड़ खनिज की राशि में दो वर्ष की करीब दो करोड़ रुपए का नियम विरुद्ध ठेकेदार को लाभ दिया	जांच चल रही है
प्रभात पाराशर	आयुक्त नगरनिगम इंदौर	वाहनों की खरीदी में 5 लाख से अधिक का भ्रष्टाचार	जांच चल रही है
गोपाल रेड्डी	कलेक्टर इंदौर	शासन को राजस्व की हानि, अवैध कॉलोनाइजरों को अनुचित लाभ पहुंचाने से शासन को आर्थिक हानि	जांच चल रही है
अनिता दास	प्रमुख सचिव ग्रामोद्योग	उन तथा सिल्क साड़ियों की खरीद में भ्रष्टाचार	जांच चल रही है
दिलीप मेहरा	प्रमुख सचिव लोकनिर्माण	कार्यपालन यंत्री से अधीक्षण यंत्री की पदोन्नति में भ्रष्टाचार एवं अनियमितताएं	जांच चल रही है
मोहम्मद सुलेमान	कलेक्टर इंदौर	कॉलोनाइजरों को अवैध लाभ पहुंचाना	जांच चल रही है
टी. राधाकृष्णन	प्रबंध संचालक, बीज निगम	दवा खरीदी में अनियमितताएं	जांच चल रही है
देवराज बिरदी	प्रमुख सचिव आवास एवं पर्यावरण	इंदौर की महू तहसील में खेती की जमीन का उपयोग आवासीय करके आवासीय कालोनी की लेआउट स्वीकार कर मेसर्स डिवाइन बिल्डर्स प्रा.लि. को लगभग 20 करोड़ रुपए का अवैध लाभ पहुंचाया	जांच चल रही है
एस.एस. उप्पल	आयुक्त नगर निगम	अवैध तरीके से 5 लाख रुपए लेकर भू-माफियाओं को भवन अनुज्ञा दी गई	जांच चल रही है
अरुण भट्ट	कलेक्टर झाबुआ	पेटलावद नगर की शासकीय आबादी भूमि का इंदौर कमिश्नर के लिखित आदेशों की अवहेलना कर भारी मात्रा में रिश्वत लेकर निजी भूमि में अदला-बदली	जांच चल रही है
निकुंज श्रीवास्तव	कलेक्टर खंडवा	पद का दुरुपयोग एवं भ्रष्टाचार	जांच चल रही है
एम.के. सिंह	आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र	3 करोड़ का मुद्रण कार्य 8 करोड़ रु. में कराया	जांच चल रही है
एम.ए. खान	एम.डी. म.प्र. राज्य बीज व फार्म विकास निगम आयुक्त मंडी बोर्ड	भ्रष्टाचार एवं गंभीर अनियमितताएं करना, मंडियों के सचिवों की नियुक्ति में अनियमितताएं निलंबन के मामले में नियम विरुद्ध कार्य किया जाना	जांच चल रही है
संजय दुबे	सीईओ जिला पंचायत	वर्ष 98-99 मे शिक्षाकर्मियों के चयन में अनियमितता	जांच चल रही है
रामकिंकर गुप्ा	सीईओ इंदौर विकास प्राधिकरण	योजना क्रमांक 54 टर्मिनल एवं बस स्टैंड बनाने हेतु 10एकड़ भूमि के आवंटन में मे. श्रीराम बिल्डर्स को 100 करोड़ रुपए का अवैध लाभ पहुंचाया	जांच चल रही है
एम.के. वार्ष्णेय	आयुक्त नगर निगम ग्वालियर	सम्पत्ति कर के प्रकरणों का अनाधिकृत निराकरण में निगम को आर्थिक क्षति	जांच चल रही है
आर.के. गुप्ता	कलेक्टर उमरिया	निविदा स्वीकृति में अनियमितताएं	जांच चल रही है
एंटोनी डिसा	आयुक्त हाउसिंग बोर्ड	निविदा स्वीकृति में अनियमितताएं	जांच चल रही है
केदारलाल शर्मा	प्रशासक, नपा खंडवा	सेंट्रीफयूगल पम्प खरीद में अनियमितताएं	जांच चल रही है
शशी कर्णावत	सीईओ, मंडला	पद का दुरुपयोग व भ्रष्टाचार, राजीव गांधी जल ग्रहण मिशन के अंतर्गत बीज एवं पौधों की खरीदी में वित्तीय अनियमितता	जांच चल रही है
विवेक अग्रवाल	कलेक्टर इंदौर	झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर ब्रिक्स प्रोत्साहन राशि के रुप में 11 लाख 50 हजार 400 रुपए प्राप्त कर कार्यालयीन उपयोग हेतु प्राप्त 21 लाख रुपए से भी अधिक राशि का मनमाना उपयोग करना	जांच चल रही है
डॉ. पवन शर्मा	उपायुक्त नगर पालिका निगम ग्वालियर	पद का दुरुपयोग कर न्यू दर्पण कालोनी ग्वालियर में बगैर रोड निर्माण कराए ठेकेदार को 5 लाख 655 रुपए का भुगतान किया	जांच चल रही है

आईपीएस अधिकारीः इंडियन (क्राइम) प्रोटेक्शन सर्विस

डॉ. राजेंद्र प्रसाद	एस.पी. सीहोर	स्वीकृत राशि में दबाव डालकर 20 प्रतिशत राशि कमीशन बतौर प्राप्त करना	जांच पूरी निर्णय का इंतजार
डी.के.आर्य	एस.पी. राजगढ़	थानों को नीलाम करने एवं ट्रांसफर में व्यापक भ्रष्टाचार	जांच चल रही है
ए.के. जैन	डीआईजी	रिश्वत लेना लंबे समय तक ट्रांसफर न करना पुलिस वेलफेयर में प्रधान आरक्षक स्तर के अधिकारी नियुक्त करना	जांच चल रही है
जयदीप प्रसाद	एस.पी. भोपाल	चार साल बाद भी कोर्ट के समक्ष खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना	जांच चल रही है
आरपी बिसौने	सेनानी,10वीं	भ्रष्टाचार व पद का दुरुपयोग वाहिनी	जांच चल रही है
एन.के. त्रिपाठी	परिवहन आयुक्त	पेंशन व ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना	प्रतिवेदन प्राप्त निर्णय का इंतजार
राजेश गुप्ता	सीईओ खंडवा	जिला पंचायत में सामग्री खरीदी में भ्रष्टाचार	जांच चल रही है

आईएफएस अधिकारीः (इंडियन फारेस्ट ईटिंग सर्विस)

डीव्ही कपिल	डीएफओ, रायसेन	अवैधानिक लीज के संबंध में असत्य एवं भ्रामक प्रस्ताव प्रस्तुत कर पदीय कर्त्तव्यों का दुरुपयोग	जांच चल रही है
बीएम अन्नगिरी	डीएफओ, इंदौर	वन क्षेत्र में मोरों को पीने का पानी व खाने के लिए ज्वार-बाजरा उपलब्ध कराने, आवंटित राशि में भ्रष्टाचार व झूठे वाउचर बनाकर पैसा हड़प जाना	जांच चल रही है
कमलेश चतुर्वेदी	सीईओ, रीवा	सीमेंट खरीदी में अनियमितता पाए जाने पर विभागीय जांच की संगठन स्तर में अनुशंसा की गई	जांच चल रही है

भारत का गणतंत्र दिवस अमर रहे
सभी राष्ट्रवासियों को
गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं
सरपच सचिव
ग्राम पंचायत, काला आम खुर्द जि. खंडवा

गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रवासियों को
ग्राम पंचायत डामिया की ओर से
हार्दिक शुभकामनाएं
माखनसिंह सचिव
सरपंच
ग्राम पंचायत डामिया
जिला खंडवा

भारत का गणतंत्र दिवस अमर रहे
सभी राष्ट्रवासियों को
गणतंत्र दिवस की
हार्दिक शुभकामनाएं
सरपच सचिव
ग्राम पंचायत, आशापुर

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार छीनो और लूटो गारंटी योजना

लूट सके तो लूट, पूरी है छूट

द ग्रेट जॉब रॉबरी, धार ग्रा. यां. सेवा दिल्ली की जांच एजेंसी की टीप

पूरे भारत में ग्रामीणों को 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी योजना, ग्रामीण रोजगार छीनो और लूटो योजना बन गई है। इंदौर जिले में जिस दर पर रोजगार दिया जा रहा है उस दर पर कोई भी मजदूरी करने को तैयार नहीं है। यही हाल नीमच और मंदसौर जिले का भी है, जहां शासन द्वारा जो मजदूरी दर भुगतान किया जा रहा है वो बाजार दर से कम होने के कारण वहां कोई काम पर जाने को भी तैयार नहीं है।

इसके विपरीत जहां मजदूरी दरें शासन की बाजारदरों से ज्यादा हैं, वहां पर यह गारंटी योजना मजदूरों को रोजगार देने की अपेक्षा रोजगार छीनने का काम ज्यादा काम कर रही हैं, अर्थात् मजदूरों का कागजों पर भुगजान कर ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा के उपयंत्री, सहायक व कार्य. यंत्रियों द्वारा सरपंचों, पंचायतों के सचिवों, जनपदों व जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों द्वारा मिलजुलकर झूठे अंगूठे व उल्टे-सीधे हस्ताक्षर कर खुले में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की जा रही है।

इस संबंध में धार जिले की जांच करने दिल्ली से जो एजेंसी आई थी उसने धार के उपयंत्रियों द्वारा की गई भारी जालसाजियों से डकारे गए रुपए138 करोड़ के कार्यों के बारे में लिखा है 'द ग्रेट जॉब रॉबरी' (विशाल रोजगार डकैती)। धार ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा जिसमें बड़कुल.... पर आरोप है कि उसने रुपए 138 करोड़ में से अधिकांश डकार लिया, अधिकांश विकास खंडों में किए जाने वाले सरकारी कार्यों को सरपंचों और उपयंत्री व सहायंत्रियों में कागजों पर काम देना दिखाकर अधिकांश फर्जी अंगूठों से दिया जाने वाले धन डकार लिया गया। कार्य दिखाने के लिए अधिकांश कार्यों को डम्परों और खुदाई मशीनों से पूरा करवा कर ओने-पोने भुगतान कर दिया।

यही हाल इंदौर संभाग के पूरे जिलों के ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा के संभागों में मनावर, धार, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, बुरहानपुर, अलीराजपुर में अरबों रुपए का भ्रष्टाचार इनके कार्यपालन यांत्रियों से लेकर सहायंत्रियों, उपयंत्रियों सरपंचों जनपदों के मु.का. अधिकारियों, अध्यक्षों, जिला पंचायतों के मु.कार्य अधिकारियों और अध्यक्षों के साथ मिलकर किया है, जिन्हें जिलाधीशों ने भी आंख मींचकर भुगतान करवा कर खुलकर लूटपाट ही हुई है। इसमें संभागायुक्त को भी अनेकों शिकायतें मिलने के बावजूद इनमें कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो हर प्रशासनिक अधिकारी को भी संदेहास्पद बना देता है।

इस संबंध में उज्जैन संभाग की स्थिति भी कमोबेश ऐसी ही है। बस अंतर इतना सा है कि जहां इंदौर संभाग में धार, झाबुआ, अलीराजपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी 6 जिले आदिवासी जिलों की श्रेणी में आते हैं, वहीं उज्जैन संभाग में मात्र रतलाम जिले व देवास जिले के कुछ विकासखंडों में ही आदिवासी निवास करते हैं। उज्जैन संभाग के शाजापुर, देवास, उज्जैन, रतलाम जिलों में भी इसी प्रकार के भ्रष्टाचार की सूचनाएं बड़े पैमाने पर प्राप्त हुई हैं।

पूरी ग्रामीण रोजगार छीनों और डकारो गारंटी योजना में समय माया ने अपने पूर्व के संस्करणों में रा.ग्रा. रो. गा. योजना में कैसे होगा भ्रष्टाचार, बिल्कुल वैसे ही पूरे देश में इस योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस संबंध मे इस विभाग के अधीक्षण कार्यालय में जब बात की गई तो वहां के अधिकारियों ने यह माना कि जैसे समयमाया ने वर्षभर पूर्व जो लिखा था हर जिले में वैसे ही भ्रष्टाचार किया जा रहा है। सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि इस रोजगार गारंटी में जिन ग्रामीणों के कार्ड बन चुके हैं वे रोजगार प्राप्ति के चक्कर में अपने निवास स्थानों पर ही कार्य करने के इच्छुक होने के कारण **शेष पेज 2 पर**

चार्टर्ड बनाम करप्ट एकाउटेंट जिम्मेदार है जालसाजियों के लिए

(अ) सत्य है 99 कं. झूठी है, बैलेंस शीट

करप्ट एकाउंटेंट से पैसा देकर कैसे भी काम करा के प्रमाणित करवा लो

भारत में हाल ही के महीनों में सामने आया सत्यन के घोटाले के लिए सच्चे अर्थों में तो चार्टर्ड बनाम करप्ट एकाउंटेंट ही जिम्मेदार हैं। जो बिना किसी वास्तविकता के कंपनी के अंकेक्षण करते रहे और झूठी रिपोर्टस पर हस्ताक्षर कर सील-सिक्के ठोंक कर न केवल आयकर, कस्टम एक्साइज व अन्य शासकीय कार्यों, राजस्व की वसूली, न्यायालयीन प्रक्रिया के साथ तो जालसाजी करते ही हैं, सबसे बड़ी जालसाजी की जाती है बैंकों, वित्तीय संस्थाओं से झूठे दस्तावेजों के आधार पर बड़े-बड़े अरबों रुपए के ऋण लेकर डकार लिए जाते हैं। निवेशकों से छल कपट के आधार पर अरबों रुपए का निवेश इन्हीं जालसाज करप्ट एकाउंटेंटों के झूठे छल कपटपूर्ण दस्तदावेजों के आधार पर प्राप्त कर लिया जाता है।

करप्ट एकाउंटेंटों की जालसाजियों के परिणाम स्वरूप ही बैंकों वित्तीय संस्थानों से लेकर 90% निवेशकों का पैसा न केवल भारत में वरन् पूरे विश्व में अस्थिरता की भंवर में फंसा होता है। भारतीय बैंकों की कुल 5000 अरब की डूबत में 1980 से लेकर 2005 तक 90% इन चार्टर्ड एकाउंटेंटों का ही हाथ था। अधिकांश शेयर मार्केट की उच्चावचनों कं. की वित्तिय स्थितियों, लाभांशों को दिखाने बांटने में चार्टर्ड एकाउंटेंटों का प्रमाणीकरण ही सर्वोच्च होता है।

वर्तमान में भारतीय शेयर मार्केट की टॉप लिस्टेड 20कं. जो सूचकांक के लिए जिम्मेदार है, यदि शासकीय अंकेक्षकों की पेनल से अंकेक्षण करवाएं तो 50% से ज्यादा सच्चाइयों के सामने आने पर सूचकांकों के निर्धारण की सूची से बाहर करनी पड़ेगी।

प्रदेश के कंपनी रजिस्ट्रारों से लेकर देश की कंपनी मामलों की विधि मंत्रालय की समिति को चाहिए कि जिन मामलों में रुपए 100 करोड़ से ज्यादा का पूंजी निवेश हुआ है उन्हें कंपनियों के निर्धारित आंतरिक और बाहरी अंकेक्षकों के अतिरिक्त उनका विधि मंत्रालय द्वारा अंकेक्षकों की पैनल निर्धारित कर उनका आंतरिक और बाहरी अंकेक्षण भी करवाए सकती है।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान को अपनी आधारभूत परिभाषा- चार्टर्ड एकाउंटेंट केवल रखवाली करने वाला श्वान है। काटने या भौंकने के लिए नहीं को ही बदलकर चार्टर्ड एकाउंटेंट राष्ट्र और इसकी जनता, निवेशकों और शासकीय कानूनों की रक्षा करने वाला साथ ही जिस संस्था में नियुक्त किया गया है उसके लेखों की अनियमितता को दूर कर सभी के हितों की रक्षा करने, चौकसी करने वाला श्वान होना चाहिए। कर दी जानी चाहिए, क्योंकि उसकी कलम से लिखा गया हर शब्द जनता, निवेशकों, वित्तीय संस्थानों, शासकीय कानूनों के जीवन का आधार होता है। भारतीय चार्टर्ड एकांउटेंट संस्थान को इस जिम्मेदारी की समझ कर अपनी मूल परिभाषा और उद्देश्य से परिवर्तन आज नहीं तो कल करना ही होगा।

भारतीय कंपनी मामलों और विधि मंत्रालय के भी भारतीय कंपनी अधिनियम 1958 में भी इस प्रकार की जालसाजियों को रोकने, सार्वजनिक निर्गम वाली कंपनियों में जनता का धन लगा होने के कारण उस पर सूचना का अधिकार अधि. 2005 लगा दिया जाना चाहिए। ताकि न केवल निवेशक अंशधारी वरन, वित्तीय संस्थान भी उसके क्रियाकलापों पर नजर रख सकें। सत्यम जैसी जालसाजीपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

जहां तक चार्टर्ड एकाउटेंटों का सवाल है तो वह शासकीय कानूनों का रखवाला नहीं वरन् शासकीय कानूनों की खामियों का फायदा उठाने वाला अपनी कलम के झूठे प्रमाणीकरण से शासकीय संस्थाओं वित्तीय संस्थानों, निवेशकों के साथ ही कानूनी प्रक्रियाओं में कानून को धता बताते हुए अपनी अवैध कमाई करने वाला जालसाज सफेदपोश, कानूनी डकैत बन चुका है। जो कदम-कदम जाली प्रमाणपत्रों, जाली प्रमाणीकरण से अपनी कमाई कर शासकीय राजस्व में हर वर्ष अरबों रुपए की सेंध लगा रहा है और सबके साथ विश्वासघात कर रहा है।

भारत की बड़ी से बड़ी रिलायंस, टाटा, बिरला, भारती से लेकर छोटी से छोटी कंपनियों जो सार्वजनिक निर्गम या सार्वजनिकर पूंजी के निवेश के दम पर चल रही है का यदि शासकीय अंकेक्षकों की टीम से अंकेक्षण करवा दिया जाए तो न केवल अरबों रुपए की आयकर चोरी से लेकर कस्टम एक्साइज, विक्रय कर, सम्पत्तिकर तक की चोरियां न केवल पकड़ में आएगी, वरन कई रिलायंस भारती जैसे दिग्गज भी अर्श से फर्श पर आ जाएंगे। न केवल शासन में बैठे दिग्गजों, मंत्रियों, न्यायाधीशों वरन जनता के साथ मोबाइल फोन काल्स में जालसाजी से वसूली से लेकर सैकड़ों प्रकार के अन्य छलकपट, बिजली, पानी की चोरी से लेकर नगर निगमों, पालिकाओं के सम्पत्तिकर, मनोरंजनकर, होर्डिंग डिस्प्ले टेक्स, अवैध अरबों की सम्पत्तियों के राष्ट्रीय स्तर पर कर चोरी के मामले तक सामने आ जाएंगे। शेयर मार्केट में जो जाली लाभों की घोषणा आदि की पोल खुल जाएगी।

बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन सच्चाइयों को जानकर पहले कुछ समय तक कांपेंगा पर बाद में उसकी साख विश्व स्तर पर न केवल स्थापित हो सकेगी, वरन् अमेरिका जैसी बैंकों के दिवालिया होने की घटना भी मुश्किल से ही स्थान ले पाएगी।

ग्राम पंचायत पाड़ल्या की ओर से
राष्ट्र के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं
सरपंच सचिव
ग्राम पंचायत पाड़ल्या जिला खंडवा

गणतंत्र दिवस पर सभी को शुभकामनाएं
ग्राम पंचायत
मदनी
सरपंच, सचिव
उपसरपंच
सभी पंच

राष्ट्र के गणतंत्र दिवस पर जनपद पंचायत खालवा की ओर से
समस्त राष्ट्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
अध्यक्ष उपाध्यक्ष के.के. उके
जनपद पंचायत खालवा जि. खंडवा

रुपए 1902 करोड़ का अनुपूरक बजट और 100 दिन की कार्य योजना

3 माह में होगा वास्तविकता में रुपए 500 करोड़ का काम

म.प्र. की 13वीं विधानसभा के प्रथम सत्र में जो अनुपूरक मांगों के लिए रुपए 1902 करोड़ 94 लाख 38 हजार का अनुपूरक बजट स्वीकृत किया गया, ताकि चुनावी खर्चों की भरपाई की जा सके, निष्कर्ष में प्रदेश गया, ताकि चुनावी खर्चों की भरपाई की जा सके। निष्कर्ष में प्रदेश के अधिकारियों को ही अगर कमाई नहीं होगी तो कहां से चंदा देंगे। जोबट स्वीकृत किया गया उसके पश्चातवर्ती विश्लेषण पर एक झलक-

अन्य मदों में प्रावधान-निपटारा और डकारो

* मध्याह्न भोजन– रुपए 58 करोड़ योजना का क्या हश्र हो रहा सभी जिलों के सीईओ से लेकर ग्राम पंचायतों के सरपंचों और सचिव को ही भोजन मिल जाए, ग्रामीण स्कूली बच्चों को ये लालच देकर भी स्कूलों की तरफ आकर्षित इसलिए नहीं किया जा सका, क्योंकि सरकारी सांडों जिसमें स्कूली शिक्षक भी थे स्वयं की भोजन व्यवस्था में लग गए।

* मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना- रुपए 12 करोड़ मजदूरों की सुरक्षा के नाम पर श्रम विभाग में बैठे सरकार और पांडे जैसे उपायुक्तों से लेकर श्रम निरीक्षकों तक चरने से कुछ बचे तो मजदूरों की सुरक्षा की बात उठे।

* बालिकाओं को सायकिलें- रुपए 17.42 करोड़ ग्रामीण बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए दी जाने वाली सायकलों का ये पैसा जिला समन्वयक, सहायक आयुक्त जो आदिवासी जिलों में बैठे हैं से लेकर ग्रामीण स्कूलों के प्राचार्य झूठे व्हाउचर लगाकर ये पैसा भी पूरा डकार जाएंगे, क्योंकि अब जब शिक्षा सत्र समाप्ति पर है तो किसे सायकल देना है सायकलें तो जुलाई-अगस्त में बंटती है।

* लोकनायक जे.पी. सम्मान रुपए 8.75 करोड़- किसी को भी सम्मान देने से पूर्व ही सभी हरामखोर नेता और अधिझकारी सम्मान के पात्र व्यक्तियों का इतना अपमान कर चुके होते हैं, फिर सम्मान और पुरस्कारों के संबंध में इतनी टांग खिंचाई होती है कि सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को इन धूर्त जालसाज नेताओं और अधिकारियों के चेहरों ने नफरत हो जाती है, यही नफरत इनको यह राशि डकारने का सुअवसर प्रदान कर देती है।

* मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान- रुपए 7 करोड़- मु.मं. शिवराज के चारों तरफ घेरे रखने वाले राक्षसों की फौज जिसमें नेता और अधिकारी होते हैं किसको स्वेच्छानुसार कहां और कब कागजों पर दिलवा कर डकार लेगी, वास्तविक हितग्राही इनाम। अनुदान के चक्कर में जिलाधीश कार्यालयों में बैठे जालसाजों की मीठी बातों में आकर कितना बर्बाद करेंगे, लुटाऐंगे यह इतिहास साक्षी है और इस आवंटित धन की बंदरबाट भविष्य के गर्भ में।

* लाड़ली लक्ष्मी योजना रुपए 10 करोड़- लाड़ली लक्ष्मी योजन में गरीब लड़कियों के जन्म पर रुपए 1 लाख की एफडी देने की योजना है अर्थात् रुपए 10 करोड़ में 1 हजार लड़कियों लखपति बनाई जाएंगी। पाठक जानते हैं कि इस सरकारी पैसे को वसूलने में या प्राप्त करने में कितने गरीब वस्त्रहीन कर देंगे, सरकारी कर्मचारी, स्वयं लखपति बनेंगे।

* सहकारी विकास योजनाएं रुपए 4 करोड़- म.प्र. के सहकारिता विभाग के भ्रष्टाचार से गांवों से लेकर शहरों तक के लोग जो इसका शिकार हुए हैं इसमें बैठे धूर्त जालसाजों से क्या और कैसी सहायता मिलती हैं।

* जनसंपर्क रुपए 17.48 करोड़- इस राशि का भरपूर सदुपयोग होगा, समाचार पत्रों को अपने कुकर्मों की सच्चाई उजागर न हो, इसके लिए अपनी प्रशंसा अपनी उपलब्धियों के आने वाले चुनाव के लिए विज्ञापन बांटकर इसमें श्री मनोज श्रीवास्तव जनसंपर्क आयुक्त अपने खास चहेतों को विज्ञापन बांटकर उपकृत करेंगे।

*विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास 27.55 करोड़- पिछले 60 वर्षों आदिवासियों और हरिजनों के विकास के नाम पर हजारों करोड़ डकारने के बाद आदिवासियों को लंगोटी से कपड़े नहीं पहना पाए- 3 माह में रुपए रुपए 27.55 करोड़ का तो मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव से लेकर जिलों के जिलाधीशों, नीचे जिलासंयोजकों और वहां बैठे गिद्ध महिला पुरुष बाबुओं, छात्रावासों के अधीक्षकों तक बैठी लंबी चौड़ी गिद्धों की फौज के लिए जो हजारों करोड़ हर साल डकारते हैं नास्ते के लिए भी पूरा नहीं पड़ेगा।

* भू-अभिलेखों का आद्यतन करना व ऋण पुस्तिका का निःशुल्क वितरण रुपए 10.23 करोड़ भू-राजस्व मे बैठे पटवारियो से लेकर नायब तहसीलदारों, तहसीलदारों, उपजिलाधीशों, सहायक जिलाधीशों, जिलाधीशो, इनके बाबुओं से वाचक, अधीक्षकों तक सबका खेल अभिलेखो मे हेरफेर जालसाजियों से कमाई का ही है, यह 6 दशाब्दियों में कभी अध्यापन नही हुआ तो कभी माह में इन श्वानों से कैसे उम्मीद की जा सकती है।

ये सब अन्य मदों में प्रावधान का वितरण था मुख्य मदों में-

रुपए 493 करोड़ बिजली के लिए- यह तो एक चमक में ही साफ हो जाएगा, फिर विद्युत मंडल में पांच कंपनियां बनाकर जबसे इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के गिद्धों को मुख्यालय में बैठाया गया है, इन हरामखोरों ने अपनी लूटपाट और अवैध वसूलियों के चलते बर्बादी ही की है, जिस शाख पर बैठ जाए अंजामें गुलिस्ता क्या होगा, इस प्रदेश की जनता देश और विश्व भी इंटरनेट पर चमकने पर देख लेता है।

- रुपए 168 करोड़ खाद्यान्न के लिए- सत्ता के तंत्र में बैठे गिद्धों का पेट भर जाएगा, तो गरीबों को मिलेगा न ये वो पेटू हैं जिनका पेट 60वर्षों में नहीं भरा तो तीन माह में तो नास्ता भी नहीं कर पाएंगे, जाचे वो नागरिक आपूर्ति का एम.डी. विवेक अग्रवाल हो, सचिव प्रधान सचिव, जिला आपूर्ति अधिकारी, खाद्य निरीक्षक, उचित मूल्य की दुकानों की समीतियां, सह. संस्थाएं आखिर मुखैरों की ये श्रृंखला को तो डकार आए।

- 90 करोड़ ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन- जहां अरबों रुपए की स्तरहीन शीघ्र समय बाधित होने वाली औषधियां कमीशन डकारने, उत्पादकों को लाभ पहुंचाने के लिए खरीदी जाती हों वर्षो से प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में डाक्टर्स ही न हो और उनका वेतन भी निकाल कर डकार लिया जाता हो, निजी चिकित्सालयों में ग्रामीण चिकित्सा करवाने में अपनी जमीनें गिरवी रखकर इलाज करवाएं इसके विपरीत उनकी चिकित्सा का अंत्योदय, दीनदयाल योजना में रुपए 20 हजार से डेढ़ लाख तक के इलाजों का पैसा सीएमओ और नर्सिंग होम्स डकार जाएं। वहां रुपए 90 करोड़ का क्या हश्र होगा पाठक अंदाज लगा लें।

- रुपए 212 करोड़ पेयजल के लिए- प्रदेश के कुछ जिले सूखे की चपेट में तो हैं ही विशेषतौर पर मालवा के जिलों और विंध्याचल के पठारी जिलों- पन्ना, छतरपुर, दमोह, सागर में भी शुद्ध से पानी की परेशानी रहती ही आई है। पानी पिलाने के नाम पर 212 करोड़ में अगले तीन माह में वास्तविखता में रुपए 52 करोड़ भी खर्च हो जाएं तो भगवान का भी जनता को धन्यवाद देना चाहिए। इससे लो.स्वा. यांत्रिकीय से लेकर 14 निगमों, 37 पालिकाओं, 250 से ज्यादा जनपद पंचायतों, 23000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को मिलने वाली अपनी **शेष पेज 2 पर**

शास. अधिकारियों ने पहले विधानसभा चुनाव में दिया अब लोकसभा में देंगे, उसके लिए ये अनुपूरक, पूर्तिकारक होगा

सहकार-अधिकारी मिलकर करो सदस्यों का बंटाढार

सहकारिता,सहकारिता विभाग है, जालसाज कर, सहकारिता में अधिकारी शोषण न करें, तो सर्वश्रेष्ठ व्यवसायिक संगठन 'बिन सहकारी नहीं उद्धार' सहकारिता कर सकती है, आसानी से सदस्यों का बेड़ा पार। इसके विपरीत सहकारिता के अध्यक्ष,सचिव, उपाध्यक्ष व कार्यकारिणी सदस्यों की व्यक्तिगत लाभ कमाने की इच्छाएं जालजासियों और सदस्यों का शोषम ही जिनकी नियति हो तो फिर बन जाती है, लूटने का आधार।

सहकारी साख संस्थाओं, गृहनिर्माण संस्थाओं, ग्रामीण सहकारी संस्थाएं, सहकारी बैंकस, सहकारी दुग्ध उत्पादक बीज उत्पादक व अन्य सभी प्रकार शासकीय, सहकारी संस्थाएं के साथ अन्य सहकारी संगठनों में पदाधिकारियों पर जैसे ही भ्रष्टाचार से कमाई का भूत सवार होता है। वैसे ही धीरे-धीरे जालसायिों की शुरुआत हो जाती है। उसको वैधानिकता प्रदान करते चलते हैं। सहकारिता में बैठे जिला स्तर के अधिकारी पंजीयक, उपपंजीयक,अंकेक्षक, ये वो गिरोह होता है, जिन्हें सहकारितासंगठन में बैठे माफिया, गुंडों से पर्याप्त धन के बदले पूरा कानूनी संरक्षण, अंकेक्षण प्राप्त होता रहता है, जिसके चलते वे हर कदम-कदम सहकारिता के उन सदस्यों का भरपूर शोषण करते रहते हैं। अधिकांश साख, गृहनिर्माण, बैंकर्स जो बिना शासन के सहयोग के चलती है, 90% खाते, तुलन पत्र, चिट्ठा आदि तक सब जालसाजी और सहकारिता विभाग के अंकेक्षक को धन खिलाकर उसकी देखरेख में झूठे खर्चों, बिलों के आधार पर तैयार करवाए जाते हैं। चूंकि अंकेक्षक ने ही सब बनाए और बनवाए होते हैं। इसलिए ऐसी टिप्पणियां लिखी जाती हैं। अंकेक्षण प्रतिवेदन में जो आसानी से ठीक व उनका निराकरण कर दिया जाता है। नए सहकारिता अधि. में तो अब केवल पंजीयन भर का कार्य शासन का सहकारिता विभाग करता है, बाकी अब अंकेक्षण का कार्य भी संस्था के पदाधिकारियों द्वारा मनोनीत अपनी पसंदके सन दी लेखाकर अर्थात चार्टर्ड बनाम करप्ट अकाउंटेंट से अपनी मनमर्जी और अपने हिसाब से करवा लिया जाता है, जो संस्था के सदस्यों के लिए पदाधिकारियों द्वारा शोषण को भी वैधानिकता की मुहर लगाने के कार्य आती है।

इस संबंध में म.प्र. शासन का सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार के चलते, उपजिला पंजीयक, जिला पंजीयक से लेकर इनके अंकेक्षण सेल में बैठे अंकेक्षक निरीक्षक का भी हर गृहनिर्माण, साख संस्थाओं से महीना बंधा हुआ होता है। जिसके चलते वो अंकेक्षक जिन्हें इसकी नियमित जांच करना चाहिए, सदस्यों के शोषण धन के विनियम और उचित उपयोग सदस्यों के हित की देखरेख करने की जिम्मेदारी होती है, वे पदाधिकारियों के इशारे पर नाचते हुए अधिकांश खाते, लेखा जोखों को उनकेहिसाब से जोड़-तोड़ करते हुए भारी जालसाजियों को हवा देते रहते हैं।

यही कारण है कि ऐसी अनेकों संस्थाएं जो केवल कागजों पर चल रही होती हैं खुलकर शासन के सहकारिता को विकास देने के नाम पर और ऐसी ग्रामीण साख, विपणन संस्थाएं गृहनिर्माण आदि कागजों पर ही चलती पाई जाती है। इसके बाद भी शासन के सहकारिता के धूर्तों को धन मिलता रहता है और ऐसी कदम-कदम सैकड़ों संस्थाओं को ये पालते चलते रहते हैं।

बहुराष्ट्रीय कंपनी बीटी और जीएम बीजों की जालसाजी के विरुद्ध

महिला वैज्ञानिक का राष्ट्रहित में संघर्ष

मैगसाय पुरस्कार देकर मेरे हाथ में तो गोबर पकड़ा दिया गया था। पुरस्कार देकर सबको यह लगा था कि मैं चुप बैठ जाऊंगी पर मेरा यह अभियान तब तक चालू रहेगा जब तक कि भारत जैविक राज्य घोषित नहीं हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां हमें भूसा खिला रही हैं। यह बात हमें जन-जन तक पहुंचानी है। हमारी लड़ाई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ है।

यह कहना है इको फेमिनिस्ट और हरितक्रांति चला चुकी देहरादून की डॉ. वंदना शिवा का,जिन्होंने अपने इस अभियान की शुरुआत चिपको आंदोलन से की थी। दस साल लड़ाई लड़ने के बाद हिमाचल प्रदेश के जंगल बचाने में वे कामयाब रही थीं। फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय में नौकरी की पर नौकरी रास नहीं आई। देहरादून की खदानों पर शोध करने के दौरान उन्हें अहसास हुआ कि उनका एक प्रयास प्रकृति को बचा सकता है। नौकरी छोडी और रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की और 1987 में नवदानियां के नाम से आंदोलन शुरू किया। मुख्य उद्देश्य था जैविक खेती को बढ़ाना और बीजों की प्रजाति को सहेजना। डॉ. वंदना शिवा से हुई बातचीत के कुछ अंश-

इस आंदोलन की प्रेरणा कैसे मिली?

बहुराष्ट्रीय कंपनिया चाहती थीं कि हमारे खाने पर वो नियंत्रण कर लें। हमारी खेती पर लगाम कसने, कई किसान आत्महत्या कर रहे थे। कपास का उत्पादन करने वाले क्योंकि बीज इतने महंगे थे। हमने पांच बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसमें बीज बनाने वाली मोंसेटो, खाने के उत्पादन बनाने वाली कारगिल और उसके बाद प्रोसेसिंग में लगी पेप्सी और नेस्ले। हमने इन कंपनियों का विरोध शुरू किया और अभियान चलाया विलुप्त होते बीजों को बचाने का। दो बीज भी हमें मिले, हमने उसे सहेजा और उसकी प्रजातियां तैयार की। इस तरह विलुप्त हो रही तीन हजार धान की और सत्तर हजार गेहूं की किस्मों को हमने बचाया। जिसमें रागी, झंगोरा, करेनी, मासा, थपड़ा जैसी प्रजातियां थीं।

जैविक खेती पर जोर देने की वजह क्या थी?

बीटी कपास के कारण हर छह घंटे एक किसान आत्महत्या कर रहा था। पांच हजार किसानों ने अपनी जान गंवाई, क्योंकि यह इतना महंगा था। विदर्भ में हमने इसीलिए इस जैविक खेती की शुरुआत की, जिससे हमें दो साल में दस गुना आमदनी हुई और हमने अच्छा उत्पाद लोगों को दिया। हमारी कोशिश थी कि हमारे किसान सीधे मार्केटिंग करें। छह आउटलेट मुंबई, दिल्ली और देहरादून में बनाए। जाहिर था कि किसानों को आत्मविश्वास तो आया ही, उन्हें खेती में भी लाभ होने लगा।

जैविक खाद के विरोध का कारम क्या था?

ये जो विदेशी कंपनियां गेहूं का उत्पादन कर रही हैं उनका फोकस ब्रेड बनाने के लिए होता है, इसलिए वो जो गेहूं की किस्म तैयार करते हैं उसमें ग्लूटीन बहुत ज्यादा होता है। हम गेहूं के रूप में रोटी खाते हैं, जिसमें ग्लूटीन की जरूरत ही नहीं है। शायद लोगों को यह पता नहीं कि ग्लूटीन की ज्यादा मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसलिए हमें ऐसे उत्पाद की जरूरत थी जो हमारे स्वास्थ्य के हित में हो। पंजाब में जो गेहूं हो रहा है, उसमें एक प्रतिशत पोषण है। पुराने गेहूं में सिर्फ चौदह प्रतिशत प्रोटीन है। देखा जाए तो हम गेहूं, मक्की नहीं भूसा खा रहे हैं, इसलिए हमें जरूरत थी ऐसे किस्म से उत्पादन करने की जो हमारी देशी फसलें हैं और इसी के लिए हमने यह अभियान चलाया।

किस तरह से तैयार करते हैं जैविक खाद?

प्रकृति का नियम है कि कीड़े ही कीड़ों को मारते हैं पर जिस तरीके से रसायन उपयोग में लाया जाता है खेती में प्रकृति का हय नियम ही खत्म होता गया। हमने खाद, गोबर, गो-मूत्र, चारा, नीम का रस, करंज का रस जैसी वनस्पतियां मिलाकर जैविक खाद बनाने की शुरुआत की, जिससे फसलों को भी दो गुना लाभ हुआ। दरअसल **शेष पेज 7 पर**

वन परिक्षेत्र सिंगाजी की ओर से
समस्त राष्ट्रवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं

आर.आर. मोधानिया	चौधरी	आर.एस. सावनेर
वन परिक्षेत्र अधिकारी सिंगाजी वन मंडला सामान्य	सहा. वन परिक्षेत्र अधिकारी सिंगाजी वन मंडल	सहा. वन परिक्षेत्र अधिकारी सिंगाजी वन मंडल

गणतंत्र दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं
मां शारदा मेडिकल स्टोर्स
प्रो. रितुराज पांडेय मेनरोड, आशापुर

ग्राम पंचायत अमलपुरा भामगढ़ की ओर से
गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
सरपंच सचिव
ग्राम पंचायत भामगढ़
अमलपुरा जिला खंडवा म.प्र.

बेशकीमती सरकारी जमीनों को डकारने और अदला-बदली में...

भूमाफिया डकार गए अरबों की जमीनें

इसी सदी के महाघोटाले के तार नीमच से पकड़ में आए विदिशा और टीकमगढ़ में भी इस गोरखधंधे के तार बरसों से चल रहा है जमीन अदला-बदली का नापाक इस खेल में भाजपा और कांग्रेस के मठाधीश संलिप्त

भोपाल (डीएनएन)। म.प्र. में कौड़ियों के मोल की जमीन सरकार को टिपाकर बदले में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन हथियाने के गोरखधंधे का भंडाफोड़ हुआ है। एक इंच जमीन देने में आम आदमी से लंबी सरकारी कवायद कराने वाले शासन ने सरमायदारों की जमीन लेने के बाद बेशकीमती सरकारी जमीन थाली में परोसकर बांट दी। पटवा सरकार के समय हुए जमीन आवंटन के घोटाले, जगतपति समिति द्वारा की गई जांच में उजागरद्ध से भी बड़ा यह घोटाला है। इस सदी के इस महाघोटाले के तार नीमच से पकड़ में आना शुरू हुए, जहां दो सौ करोड़ रुपए से ज्यादा की बेशकीमती सरकारी जमीनों के मालिक असरदार लोगहो गए और सरकार को दी बेमोल की जमीन। इसके बाद विदिशा और टीकमगढ़ में भी जमीनों की अदला-बदली के मामले सामने आने से राजस्व विभाग के आला अफसरों की आंखें फटी की फटीरह गईं। जमीनों की बंदरबाट के इस नापाक खेल की परतें उधड़ना शुरू हुई तो पता चला कि पूरे प्रदेश में प्राइवेट जमीन देकर सरकारी जमीन हथियाने वाला रैकेट बरसों से काम कर रहा है। बस जिला बदलने के साथ जमीन के मालिक बदलते गए। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी, तो अदला-बदली के इस खेल में राजनेताओं व अफसरों दोनों के हाथ रंगे हैं। इसमें शुचिता और सुशासन देने का दावा करने वाले भाजपाइयों के करीबियों के नाम सामने आए हैं तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह ने भी अपने रिश्तेदारों को उपकृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सभी ने दोनों हाथों से सरकारी नियम-कायदों की आड़ में अपने चहेतों को जमीनों की बंदरबाट करवाई।

म.प्र. में सरकारी जमीनों के घोटाले, जमीन पर कब्जा करने के मामले तो सुने होंगे, लेकिन शासन द्वारा कौड़ियों के मोल की निजी जमीन लेकर बेशकीमती सरकारी जमीन बांटने के मामले पहली बार उजागर हुए हैं। बिच्छू डॉटकॉम की पड़ताल में मिले साक्ष्य चीख-चीखकर कर रहे हैं कि नौकरशाही व नेताओं के गठजोड़ ने किस तरह से प्रदेश के कई जिलों में सरकारी जमीनों के बदले कौड़ियों के मोल की निजी जमीन लेकर शासन को कंगाल कर दिया। इस गोरखधंधे को अब भी नहीं रोका गया, तो पूरे प्रदेश में कीमती सरकारी जमीन शासन के हाथों से निकल जाएगी।

प्रदेश में इस घोटाले की शुरुआत शासन के जमीन के बदले जमीन देने के एक नियम की आड़ में शुरू हुई। जमीनों के सौदागर माफियाओं ने इसकी आड़ में सरकार को कंगाल और निजी भूमि मालिकों को मालामाल बना दिया। अकेले नीमच जिले में सैकड़ों प्रकरणों में जमीन के बदले जमीन दी गई। इन मामलों में सरकार को किस तरह चूना लगाया गया, यह इससे ही साफ हो जाता है कि निजी भूमि मालिकों ने गांवों के अंदर की जमीन सरकार को टिपा दी और नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे व प्रमुख मार्गों वाली बेशकीमती सरकारी जमीन इन लोगों के नामे कर दी गई। नीमच जिले में सैकड़ों प्रकरणों में कंगालपतियों को करोड़पति बना दिया। नीमच में राजस्व विभाग की जांच में जैसे-जैसे मामले सामने आते गए जांच का दायरा भी बढ़ता गया। जिले में वर्ष 2001-02 से 2007-08 तक करीब 100 प्रकरण सामने आ चुके हैं। इनमें से सर्वाधिक 20 मामलों में जमीनों की अदली-बदली वर्ष 2006-07 में हुई। जबकि अपवाद स्वरूप कुछ मामले अस्वीकृत भी हुए।

नेताओं ने लिखी चहेतों के लिए नोटशीटः-

नीमच जिले में जमीनों की बंदरबांट में नेताओं का भी अहम रोल रहा। नेताओं ने जिम्मेदार पदों पर रहते हुए ऐसे लोगों को सिफारिश की, जो भू-माफिया है। नीमच-मंदसौर के कद्दावर राजनेताओं ने जमीनों के गोरखधंधे में जमीन माफिया को सहयोग के लिए लिखे गए पत्रों को देखकर इन नेताओं के भी माफिया से गठजोड़ की भी जांच होनी चाहिए।

कुछ मामलों की बानगी देखिए-

विदिशा जिला मुख्यालय पर बेतवा नदी के किनारे कांग्रेस के दिग्गज नेता के रिश्तेदार की जमीन थी। इस जमीन को अदला-बदली के नियम के तहत शासन के नामे कर दिया गया और शासन ने कांग्रेस नेता के रिश्तेदार को शहर की सबसे पॉश कालोनी अरिहंत विहार स्थित सरकारी जमीन दे दी। जानकर हैरानी होगी कि अरिहंत विहार की इस जमीन को लेने के लिए सरकारी विभागों ने आवेदन किया था, लेकिन कांग्रेस नेता के दबाव में उनका आवेदन कूड़ेदान में फेंक दिया गया और लंबी जद्दोजहद के बाद जमीन कांग्रेस नेता के रिश्तेदार को ही मिली। टीकमगढ़ जिले के कलेक्टर ने शासन को 23 दिसम्बर 08 को अवगत कराया है कि यहां भी पूर्व मंत्री सुनील नायक की हत्या के मामले में फरार कांग्रेस विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर के नाम वर्ष 1996-97 में बेशकीमती जमीन इसी अदला-बदली नियम के तहत की गई है।

नीमच जिले में पिछले दो सालों में 20 प्रकरणों में जमीन के बदले जमीन दी गई है। इन मामलों में गांव की बंजर जमीनों को भी सरकार को टिपा दिया गया और सरकार से मौके की बेशकीमती जमीन अपने नाम करा ली गई है।

नीचता देखिएः-

शासन से बेशकीमती जमीन लेने के बाद कुछ सरमायादारों की नीचता देखिए कि उन्होंने सरकारी जमीन के बदले में सरकार को दी गई अपनी जमीन भी नहीं छोड़ी। कुछ मामलों में सामने आया है कि जमीन की बंदरबाट में असरदारों ने सरकार से जमीन के बदले जमीन ले ली और अपनी जमीन भी कागजों में सरकार के नाम कर दी, लेकिन कब्जा नहीं छोड़ा। यानी सरकारी जमीन के मालिक बन गए और अपनी जमीन पर कब्जा कर शासन को ही ठेंगा दिखा रहे हैं।

अदला-बदली के सरकारी नियमः-

शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सरकारी जमीन से निजी जमीन की अदला-बदली के लिए दोनों जमीनों का समान मूल्यक ा होना जरूरी है। जमीनों की अदला-बदली में बारीकी से परीक्षण किया जाता है। यह स्थानीय प्रशासन स्तर से शुरू होता है और विभाग के मुखिया तक फाइल जाती है। राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव को ओके किए जाने के बाद जमीन बदलने के फैसले पर मोहर शासन द्वारा लगाई जाती है। शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सरकारी जमीन से निजी जमीन की अदला-बदली के लिए दोनों जमीनों का समान मूल्य का होना जरूरी है। जमीनों की अदला-बदली में बारीकी से परीक्षण किया जाता है। यह स्थानीय प्रशासन स्तर से शुरू होता है और विभाग के मुखिया तक फाइल जाती है। राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव को ओके किए जाने के बाद जमीन बदलने के फैसले पर मोहर शासन द्वारा लगाई जाती है।

इस तरह हुआ खुलासाः-

नीमच जिले में जमीनों की अदला-बदली का गोरखधंधा शिकायतों के मिलने के बाद उजागर हुआ। यह शिकायतें जागरुक लोगों ने पहले स्थानीय प्रशासन में की, लेकिन इस गोरखधंधे के कर्ताधर्ता ही जिले के अधिकारी थे, इसलिए शिकायतें दबा दी गई। बाद में यही शिकायतें राजधानी में पहुंचाई गई। नीमच के कुछ मामलों की शिकायतें राजस्व विभाग के आला अफसरों तक भेजी गई और जब यहां से जांच संबंधी कार्रवाई शुरू की गई तो पूरा मामला साफ हो गया। इसके बाद विभाग ने नीमच जिले में हुए सभी जमीन हस्तांतरणों के मामलों की सूची बुलवाई। सात साल में हुए जमीन हस्तांतरणों को बारीकी से खंगाला जा चुका है। कुछ पुराने रिकार्ड और मंगवाने की तैयारी का जा रही है।

इंदौर में म.प्र. लो.नि. के वर्तमान मुख्य अभियंता कार्यालय के चारों तरफ 300 एकड़ जमीन थी जो कि पूर्व में पत्रकार चौराहे से पश्चिम में सेंटर पाईंट पेट्रोल पम्प से पलासिया थाने और वहां से लेकर साकेत चौराहे तक थी, जिसकी वर्तमान में उस जमीन को बड़े-बड़े जादूगर न केवल निगल गए बल्कि वहां बड़े-बड़े बहुमंजिला भवन सीना ताने खड़े हैं। जिस पर किसी की नजर नहीं है। अकेले इंदौर में म.प्र. लो.नि.विभाग की सम्पत्ति पर बड़े-बड़े भूमाफियाओं का कब्जा है। एक बार पूर्व कलेक्टर मनोज श्रीवास्तव लो.नि.वि. में घुसकर जो फाइलें ले गए थे सन 03-04 में उनका अभी तक पता नहीं है। सूचना के अधिकार में इंदौर के मुख्य अभियंता को अनेकों पत्र दिए गए, जिनका जवाब वर्षों बाद अभी तक नहीं दिया गया है। इंदौर लो.नि.वि. सं.क्र. 1 के का.अ. सांवला को भी नहीं मालूम की कितनी सम्पत्तियां उनके अधिकार क्षेत्र में हैं, कितनों का किराया आ रहा है, कितनों के पट्टे समाप्त हो चुके हैं, इस भ्रष्टाचार में जिलाधीश कार्यालय ने भू-माफियाओं के इशारे पर फाइलें मंगवाकर गायब कर दी गई हैं, जिसमें अरबों रुपए की बेशकीमती जमीनें हैं।

यह कहानी केवल इंदौर की ही नहीं वरन् उज्जैन, ग्वालियर, भोपाल, जबलपुर जैसे हर संभागीय स्तर के जिलों के साथ पूरे म.प्र. की है। जिसमें जिले के हर जिलाधीश ने पिछले 40वर्षों में अपनी धूर्त, मक्कारीपूर्ण भूमिका अदा कर दोनों हाथ से धन बटोर कर खिसक लिए हैं और सरकारी सम्पत्तियों, जमीनों पर भू-माफियाओं के कब्जे करवाकर बड़ी-बड़ी रहवासी कालोनियां कटवा दी, बड़े-बड़े बहुमंजिला इमारतें खड़ी करवा दीं। भोपाल में राज एक्सप्रेस के मालिक अरुण सहलोत ने ऐसी ही जमीनों पर 50 से ज्यादा, इंदौर में भी दस से ज्यादा ऐसी ही जमीनों, बहुमंजिला इमारतें खड़ी कर बेच कर अरबों रुपए कमाया, जब पत्रकारों का ज्यादा दबाव पड़ा तो खुद ही राज एक्सप्रेस व राज टीवी चालू कर इस धूर्त ने अपनी सुरक्षा दीवारें खड़ी की, ताकि प्रशासन पर दबाव बनाया जा सके, इसमें भी भोपाल का सन 85 से अभी तक हर कलेक्टर की भूमिका संदिग्ध रही है।

इन भू-माफियाओं के तार भोपाल, ग्वालियर के आयुक्त, भू-राजस्व व सचिव व भू-राजस्व और भू-अभिलेखागार से सीधे सन 1996 से ही जुड़े रहे हैं। अदला-बदली का खेल भी पिछले 30वर्षों से चल ही रहा है।

महिला वैज्ञानिक..

पेज 6 से जारी

बहुराष्ट्रीय कंपनियां रसायन खाद तो लाईं पर जब उनके उत्पाद असफल हुए तो प्रयोग पर प्रयोग करती रहीं। कपास की प्रजाति से खिलवाड़ किया, जो खादी वह हमारे देशी बीज से अच्छा बनता है पर फैक्ट्री में चाहिए लांग स्टेबल बीज, तो बीटी कपास ले आए। हाइब्रिट के साथ अमेरिकन बोलवम आया। बोलवम को रोकने के लिए कीटनाशक आया, ये फेल हुआ तो बीटी कपास आया। एक समस्या शुरू हुई तो यह प्रयोग करते गए। यही चीज मक्का के साथ हुई। अभी आज जो बाजारों में जो मक्की बिक रही है वो जानवरों के लिए है, जिसे हम खा रहे हैं। उसमें कई ऐसे वायरस हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। इसके लिए हमने बीज नहीं खड़े किए। किसानों का अपना बीज बैंक। हमने किसानों को बताया कि अपने ही बीज से कैसे उत्पादन बढ़ सकता है। दूसरा हमने जैविक खेती के लिए किसानों को प्रशिक्षण दिया। छह लाख किसान आज हमासे जुड़े हैं जाहिर है किसान का खर्च पर भी नियंत्रण हुआ। जो पैसा उसका रसायन खाद में खर्च होता था, वो बचा। किसान को अपना माल बाजार में पहुंचाना था, इसलिए हमने उनका हाथ थामा। उन्हें आर्गेनिक और रसायन में अंतर समझाया औरयह सब हुआ नवदानियां के जरिए।

आपको रोकने के लिए धमकियां भी मिली होंगी?

मिलीं न, आज भी मिल रही हैं। लालच भी दिया ये पुरस्कार के रूप में पर हम कहां रुकने वाले थे।

कुछ और प्रजातियां जो आपने बचाई हैं?

आजहम सोलह राज्यों में काम कर रहे हैं। हम अन्न स्वराज खड़ा करते हैं। क्वाटम थ्योरी में पीएचडी करने वाली वंदना शिवा जिसका बाटनी से दूर-दूर तक नाता नहीं था आज कुछ ऐसी प्रजातियां बचाने में कामयाब रही हैं जो किसानों के लिए फायदेमंद हैं। जैसे लाल धान, जिसका उत्पादन आज किसान कर रहे हैं, जिसमें भरपूर प्रोटीन है जिसका सलाद बनता है। उसका दाना भी लाल है। ये कैंसर से रोक थाम के लिए रामबाण दवा है। जिसकी आज दवाइयों के रूप में मांग की जा रही है। देहरादून में कैंसर की रोकथाम के लिए इसके इस्तेमाल पर रिसर्च चल रहे हैं एक धान की प्रजाति हमने बचाई है जो अट्ठारह फुट की है। सबसे बड़ी बात तो धान की हमने एक ऐसी प्रजाति तैयार की है जो नमक सहन कर लेती है और उन जगहों पर जहां भूकंप के बाद जमीन बेकार हो जाती है उसे उगाया जा सकता है। उड़ीसा में उसका सफलतापूर्वक उत्पादन हो रहा है। सुनामी में तीन-चार किलोमीटर तक समुद्र का पानी आ गया था और वो जमीन खेती के लिए बेकार हो गई थी, वहां हमने इस किस्म को बोया और हमें सकारात्मक परिणाम मिले, जबकि सरकार का कहना था कि पांच साल तक यहां खेती नहीं हो सकती। हमने उस जगह पर ये बीज बांटे।

मध्यप्रदेश के लिए क्या सोचा है?

मध्यप्रदेश के इंदौर शहर में बीज बैंक स्थापित करने की योजना है और हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड की तरह मध्यप्रदेश को भी जैविक राज्य घोषित कराएं। आज सोलह राज्यों में हमारे बीज बैंक की सफलता इस बात की गवाह है कि किसान अच्छे-बुरे में अंतर समझने लगे हैं।

ग्राम पंचायत चारखेड़ा
जिला खंडवावासियों की ओर से
राष्ट्र के गणतंत्र दिवस
पर हार्दिक शुभकामनाएं

मांगीलाल ध्रुवे (सरपंच)
कौशल (सचिव)

ग्राम पंचायत चारखेड़ा

राष्ट्र के गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं

श्रीमती बिस्सो बाई (सरपंच)
संजय कुमार यादव (सचिव)

ग्राम पंचायत जोगीखेड़ा जिला खंडवा, म.प्र.

साप्ताहिक
समय माया

जिस शाख पर आई.ए.एस. बैठा, अंजामे मंडल क्या होगा?

बिजली बेच और मुफ्त बांट
बिल भरने वालों को अंधेरा

इंजीनियर भ्रष्ट थे, आई.ए.एस. महाभ्रष्टों को लूटों, खाओ से मतलब म.प्र. विद्युत मंडल में जबसे इंडियन एव्यूसिंग सर्विस के श्वानों को बैठाया गया, भ्रष्टाचार और लूट कई गुना बढ़ी बाद में लिब्राइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की आंधी में मंडल को टुकड़े-टुकड़े कर कंपनियां बनाकर इन श्वानों को प्रबंध संचालक बनाकर बैठाने से विद्युत मंडल में चारों तरफ लूटपाट की बाढ़ आ गई, इन हरामखोर मुखैरो की फौज को केवल येन-केन प्रकारेण धन वसूलने से मतलब होता है, फिर ये बी.ए.एम.ए. पास को विद्युत यांत्रिकीय का अ,ब,स,द नहीं मालूम होता, उन्हें केवल धन के प्रबंधन में इनका हिस्सा कहां और कितना होगा, उससे मतलब होता है उनकी बला से, उसमें रखरखाव के अभाव में क्या बर्बादी हो रही है, उनकी कंपनी में वर्षों से सब स्टेशनों के खम्भों पर एल्यूमिनियम और कॉपर पेंट नहीं हुआ है, अधिकांश ट्रांसफार्मर्स में ढंग से तेल, पानी और रखरखावों के अभाव में रंगरोंगन न होने केकारण जंग खा रहे हैं, उनका कार्यकाल आधा रह गया है, हो गया है, इन हरामखोरों को इस सबसे कोई मतलब नहीं, ये तो मेंटेनेंस, खरीदी में मोटा कमीशन बिजली चोरियों में मोटे, समायोजनों से धन डकारने में ही विश्वास रखते हैं।

विद्युत मंडल की सभी कंपनियों के निर्माण के बाद से इनका प्रबंधन कितना अच्छा है, इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी ने भी कंपनी अधिनियमों 1956 के प्रावधानों के अनुसार 5-7 वर्षों में एक भी बार अपनी बैलेंस शीट और लाभ-हानि खातों का प्रकाशन दो अखबारों में तो जब करवाएंगे जबकि इनकी बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते बनाए गए होंगे। अर्थात लाभ-हानि और चिट्ठे इन जालसाजों ने अपनी जालसाजी छुपाने के लिए बनाए ही। बनवाए ही नहीं गए, जबकि इन 57वर्षों में हर कंपनी में 3-4 आईएएस बदले जा चुके हैं। फिर ये यहां काम करने नहीं वरन् अपना समय पास करने और येनकेन प्रकारेण धन समेटने की नियत से ही आते हैं। जो पूर्णतः तकनीकी ज्ञान, तकनीकी संस्थान के संचालन के अभाव में पूर्णतः शून्य होते हैं, फिर आई.ए.एस. मात्र राजस्व के प्रशासकीय कार्यों के लिए बनाए गए थे, ताकि इंजीनियरिंग संस्थान चलाने के लिए फिर ये जब ऐसे संगठनों में बैठकर धूर्तता और मक्कारों के साथ वहां के कार्यपालन अधीक्षण और मुख्य अभियंताओं के जानवरों की तरह हांकते हैं तो उनके स्वाभिमान पर आघात पहुंचता है, चूंकि वो शूकर इनसे बड़े पद पर बैठा हैं तो उसकी हां में हां करते हुए जैसा वो कहता है ये तकनीकी ज्ञान और त्रुटियों को दरकिनार कर करते रहते हैं तो बर्बादी तो निश्चित ही है।

जब तक मंडल इंजीनियरों के हाथ में था वो बीस वर्ष आगे की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नियोजन करते थे, परंतु विश्व व्यापार संगठन के लिब्रालाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन से चारों तरफ किस प्रकार बर्बादी की गई उसके ह्रप में म.प्र. विद्युत मंडल की वास्तरिकता सामने है। उसको पूरी दुनिया पर थोंपने वाला अमेरिका का किस स्थिति में वह भी दुनिया देख ही रही है।

म.प्र. विद्युत मंडल ने 1995 में ही म.प्र. की कुल आवश्यकता के अनुसार प्रदेश में 2004-2007 के लिए 6999-75 में वा. सन् 07-08 के 8689 मे.वा. बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा था, जिसके बदले में मात्र 4281.14 मे.वा. बिजली मिल रही है उसमें से भी 140 मे.वा. बिजली बेची जा रही है, तो मात्र जनता को परेशान कर जानबूझकर कर्मचारियों, अधिकारियों को वेतन न देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है कि कंपनियों के पास धन का अभाव है, लागत ज्यादा आ रही है जबकि कुल लागत का हजारों गुना ज्यादा वसूली की जाने के उपरांत भी मुखेरों की नियत ज्यादा लूटपाट करने की है फिर जो मुफ्त में बांटी व बेची जा रही है तो क्यों? अनाप शनाप इंजीनियर्स, वसूली व लूट कर रहे हैं क्यों?

फिर अपने हिस्से की बिजली एनएचडी से पुनासा इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर सरदार सरोवर से ही नहीं खरीद रहे हैं जो न केवल सस्ती है, वरन् उसमें पारेषण हानि भी कम होगी, इसके पीछे मात्र छह कंपने के एनडीआईए की नीच लूटने खाने की मानसिकता है और कीमतें का षड्यंत्र है, जबकि वास्तविकता यह है कि म.प्र. विद्युत मंडल में 05/02/08 के अनुसार विद्युत मंडल की साइटों पर जो आंकडे दिए जा रहे थे उसमें ताप विद्युत गृहों में संजय गांधी की कुल क्षमता 1340 मे.वा. है, परंतु क्षमता का 67प्रतिशत सतपुरा की कुल क्षमता 290 मे.वा. परंतु क्षमता का 42 प्रतिशत ही उत्पादन कर रहे हैं। अमरकंटक के पास कोयले 80673 टन सतपुडा के पास 41568 मे.वा. बिजली प्रदेश में अंधेरा करने के बाद बेची भी जा रही है और 4414 मे.वा. की मानग की पूर्ति की जा रही है। इंदिरा सागर से 323 मे.वा. ओंकारेश्वर से 156 मे.वा. बिजली मिल रही है, जबकि कुल ताप विद्युत गृहों से 2772.5 मे.वा. के बदले मात्र 1499 मे.वा. विद्युत ही प्राप्त हो रही थी, सरदार सरोवर से 109.64 मे.वा.मिल रही है।

06/2/09 के अनुसार विद्युत आपूर्ति जो इनकी साइट दिख रही थी, संभागीय स्तर पर 22 घंटे जबकि वास्तविकता में मात्र 18 घंटे, जिला स्तर पर 18 घंटे वास्तविकता में मात्र 14 घंटे तहसील स्तर पर 13 घंटे वास्तविकता में 10 घंटे, गांवों में 10 घंटे जबकि वास्तविकता में तीन फेस को भी 6 घंटे मुश्किल से आपूर्ति की जा रही है, गांवों में सिंगल फेस को बिलकुल भी विद्युत आपूर्ति नहीं की जा रही है, यह इनकी साइट भी मानती है। इसी साइट में स्त्रोत में सी कालम में स्वीकार किया गया है कि बैकिंग/बिक्री के अंतर्गत 138.29 मे.वा. बिजली हर दिन अन्य राज्यों, बिजली उत्पादकों को आपूर्ति की जा रही है, जिले डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.एम.पी.-जीएवी.इन साइटों पर देखा जा सकता है।

अर्थात् चुनावों की समाप्ति के बाद जो चुनावों के लिए बिजली खरीदी की गई थी और बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत उधार ली गई थी, उसे खर्च और कर्ज को पूरा करने के लिए कटौती कर उल्टे ही 138.29 मे.वा. बिजली वापिस की जा रही है।

इसी साइट के अनुसार ताप विद्युत के 2056.28 मे.वा. शेष पेज 2 पर

बिना बुलाए धन वसूल कर निर्णय दे रहे हैं आयुक्त
जालसाज, मुखैरे, गिद्धों का जमावड़ा सूचना आयोग
7-7 महीने तक निर्णय नहीं, निर्णय प्राप्त करने में भी आवेदन, फिर अपील

भोपाल। म.प्र. सूचना आयोग में भी बाबुओं, स्टेनों से लेकर तीन आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त भी कदम-कदम अपनी धूर्त मानसिकता और जालसाजियों का परिचय दे रहे हैं, ये हैं इस अधिनियम की पारदर्शिता लाने और जनता को राहत देने के हक के लिए बनाए गए सूचना आयोग में कार्य करने वालों का नीच और भ्रष्ट मानसिकता का जीते जागते उदाहरण-

इंदौर निवासी वल्लभ चौहान ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इंदौर से जानकारी मांगी वहां बैठे जालसाज धूर्त, मक्कार बाबुओं से लेकर तत्कालीन क्षे.प.अ. गिरीश मोहन पाठक ने जानकारी नहीं दी। चौहान ने अपनी लगाई, राहत नहीं मिली, उन्होंने दूसरी अपील लगाई। प्रथम आवेदन दिनांक 03.01.07 को दिया गया। प्रथम अपील जिलाधीश इंदौर को, 08.02.07 को लगाई गई। मार्च 07 में दूसरी अपील लगाई गई।

अब सूचना आयोग के हरामखोरों की जालसाजी देखिए कि उन्हें बुला कर रुपए 24.04.08 अपील सुनी तो गई, चूंकि इंदौर की अपील आयुक्त इकबाल देखते हैं। उनका स्टेनो सक्सेना हर आगंतुक प्रतिवादी से लेनदेन की बात अलग बुलाकर कर लेता है, जिससे सेटिंग हो जाती है। उसमें आयुक्त इकबाल अहमद ने भी अपीलार्थी से कहा इन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि आयुक्त की व्यवस्था कर दी गई थी, इसलिए आयुक्त ने 24.04.08 को अपील सुनने के बाद भी कोई निर्णय नहीं दिया।

बाद में अपीलार्थी ने आयोग के निर्णय का 6 माह इंतजार किया, परंतु हरामखोरों को धन मिल गया था, तो निर्णय कैसे देते। निर्णय प्राप्त करने के लिए आयोग में श्री चौहान को सूचना के अधिकार में आवेदन दिया तो ये आयोग में बैठ डकार गए। आवेदक ने पुनः उसकी भी अपील आयोग में की तब जाकर इन भ्रष्टों को चैतन्यता आई और उस 24.04.08 की सुनवाई की निर्णय 20.1.09 को निर्णय देते हुए प्रतियां उपलब्ध करवाई गईं।

आवेदक श्री अजमेरा की अनेकों द्वितीय अपीलें आयोग में वर्ष भर से ज्यादा लंबित हैं, ये हरामखोर जालसाज अपीलों के पंजीयन में जालसाजी करते हुए किसी में पंजीयन में प्रतिप्रार्थी का नाम नहीं देते, दूसरा किस दिनांक में अपील की दी गई है उसकी जानकारी देते हैं तो इनके पंजीयन के पत्रों से ये मालूम नहीं पड़ता कि किसके विरुद्ध अपील स्वीकृत कर पंजीकृत की गई है।

इनके भ्रष्टाचार और जालसाजी का दूसरा नमूना किए बिना अपीलार्थी को सूचना दिए बिना ही बाले-बाले अपीलें सुनकर धन सूल कर धड़ल्ले से अपीलें निरस्त कर रहे हैं, क्योंकि इन गिद्धों को वही टुकड़े मिल जाते हैं तो ये क्यों अपीलार्थी और फिर वो भी श्री अजमेरा कैसे बुला सकते हैं। हाल ही में इन शूकरों ने 21.01.09 ने 28.1.09 लोक सूचना अधिकारी जलसंसाधन विभाग उदयन मार्ग उज्जैन और मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग उज्जैन की अपीलें एक तरफा सुनकर इन शूकरों ने धन वसूल कर निरस्त कर दी, जबकि दोनों में दोनों ही लोक सूचना अधिकारी जानकारी न देने के स्पष्ट दोषी थे।

बिना अपीलार्थी को बुलाए सूचना आयोग में बैठे गिद्ध धन वसूली कर दसियों निर्णय दे चुके हैं, क्योंकि अपीलार्थी इन भ्रष्टों की हर गतिविधि पर वहां नजर रखता है, कि पहले हर विभाग का प्रतिप्रार्थी को स्टेनो सक्सेना से मिलने के लिए कहा जाता है, जब सेटिंग हो जाती है, लेन-देन की तो चुपचाप अपीलों में स्पष्ट सूचना अधिकार का उल्लंघन होने पर भी अपीलें निरस्त कर दी जाती है।

ऐसे ही एक निर्णय में अपीलार्थी श्री अजमेरा को बिना अपील सुनने के दिनांक 29.01.09 की जानकारी का पत्र भेजे बिना अध्यक्ष एवं प्रबंध निर्देशक म.प्र. पश्चिम विद्युत वितरण कं. इंदौर की अपील को इस आयुक्त इकबाल अहमद ने शब्दों के मायाजाल में उलझा कर निरस्त कर दिया। अपीलार्थी वल्लभ चौहान को भी क्षेत्रीय कार्यालय परिवहन विभाग इंदौर के विरुद्ध दो अपीलों में भी बिना बुलाए इस मुखैरे श्वान आयुक्त इकबाल अहमद ने एक तरफा निर्णय दे दिया। आखिर मुख्यमंत्री शिव जो सत्ताधीश राक्षसी प्रवृत्ति शेष पेज 2 पर

भारतीय वित्त मंत्रालय और बैकिंग का कारनामा
जालसाजों को 600 करोड़
सत्यम पर लुटाएंगे जनता की कमाई

नई दिल्ली। 99प्रतिशत कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में भारी जालसाजियां करती हैं। सत्यम कम्प्यूटर्स लि. के मामले में ये सिद्ध होने के बाद भी रुपए 600 करोड़ का राहत पैकेज देकर कांग्रेसी जालसाज जनता से कस्टम, एक्साइज, आयकर, विक्रय कर के ह्रप में नोंची व वसूली गई राशि को सत्यम कम्प्यूटर्स लि. पर लुटाएगी, आखिर क्यों?

कांग्रेसी श्वानों का पैसा कहीं न कहीं सत्यम में उलझा है, उससे और भी कई राजनीतिक पार्टियों के मंत्री भी होंगे विशेषतौर पर इस दक्षिण भारत की कंपनी में संभवतः पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम का पैसा भी फंसा हुआ होने के साथ बड़ी शेयर होल्डिंग भी होगी, यही कारण था कि उसके पूर्व प्रबंध संचालक राजू के इतने बड़े कांड पकड़ में आने के बाद भी अपने वित्तमंत्री होने का फायदा देते हुए अपना पैसा निकालने और वसूली करने के लिहाज से ही यह इन हरामखोर सफेदपोश डकैतों ने जनता के धन का थोड़ बहुत नहीं वरन् रुपए 600 करोड़ का राहत पैकेज सरकार दे रही है। जनता का धन इनकी बपौती नहीं जो कहीं भी और कैसे भी लुटाया जाए। ये भ्रष्टाचार की गंदगी चाटने वाले गरीबों से निवाला छीनकर पेट्रोल, डीजल पर 200 से 500 प्रतिशत लाभ विक्रय कर कस्टम एक्साइज वसूल कर कैसे अपने पेट भरने के लिए लुटाया जा रहा है ये उसका ठोस व पुख्ता प्रमाण है।

प्रतिबंधात्मक सूचना

इस समाचार पत्र एवं वेबसाइट में प्रकाशित समाचार सामग्री का पूर्ण-अपूर्ण या उसके आधार पर बनाये गये अन्य समाचार, टीवी समाचारों, टीवी एपिसोड, इंटरनेट साइटों पर नगर, प्रदेश व राष्ट्र या राष्ट्र के बाहर विश्व में किसी समाचार पत्र पत्रिका, टीवी समाचारों, डाक्यूमेंट्री या धारावाहिकों में बिना लिखित आदेश व अनुमति के उपयोग न करें. अन्यथा कॉपी राइट एक्ट के अंतर्गत इन्दौर न्यायालय में क्षतिपूर्ति एवं कानूनी कार्यवाही की जा सकती है एवं किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र इंदौर रहेगा। इस समाचार पत्र की प्रतियां लेकर कुछ जालसाज ढोंगी पत्रकार होने का ढोंग कर पैसे, चंदा, सम्मेलनों के नाम पर धन वसूली करने की शिकायतें मिल रही हैं. ऐसी किसी भी अवस्था में आप सीधे मोबाइल पर चर्चा कर स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं. अन्यथा सीधी पुलिस और कानूनी कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र हैं.

आज्ञा से
प्रधान संपादक

स्वामित्वाधिकारी, प्रधान संपादक एवं प्रकाशक अजमेरा एस.पी. कुमार के लिए मीडिया वर्ल्ड कम्यु. 299-अंबेडकर नगर, इन्दौर के लिए नवनीत प्रिंटर्स जेल रोड, इन्दौर द्वारा मुद्रित. बडवानी प्रतिनिधि-नरेश नायक मो. 94250-90602, भुपेन्द्र बिल्लोरे मो.99934-49774
कम्प्यूटराईजेशन- सुनील जोशी 93290-40982, भोपाल प्रतिनिधि एस.के. भारद्वाज मो.94256-37958, इन्दौर कार्या. फोन 2304377 मो. 93007-55803